● वर्ष-2
● अंक-184
रायपुर, शनिवार
25 मार्च 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmailÐcom

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे, सदस्यता रद्द

भाजपा-कांग्रेस के बीच वार-पलटवार, विपक्षी एकता भी दिखी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को सूरत के एक अदालत ने मानहानि मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। लेकिन इस मामले को लेकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। आज लोकसभा सचिवालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, किसी भी सदस्य को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा होने पर अयोग्य घोषित किया जाता है। व्यक्ति कारावास की अवधि और एक और छह साल के लिए अयोग्य होता है।

राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही और मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी के पिता कौन हैं। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा क़ायम रखता है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वह नेहरू नाम क्यों नहीं रखते. लेकिन आपको किसी जज ने दो साल की सज़ा नहीं दी। आपको संसद से डिस्क्वालिफाई नहीं किया. राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी और मेहूल चौकसी पे सवाल उठायाज। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए? आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए, इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा जिसे आप ख़त्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज़ बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक ख़ासियत है आप जैसे कायर, सत्तालोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए।

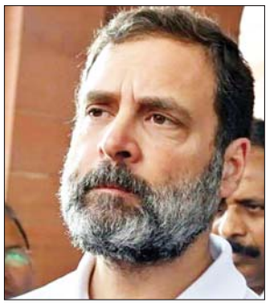

कांग्रेस का प्रहार

सांसद के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा उन्हें अयोग्य ठहराने के सभी तरीके आजमाए। जो सच बोल रहे हैं उन्हें वो रखना नहीं चाहते लेकिन हम सच बोलते रहेंगे। हम जेपीसी की मांग जारी रखेंगे, जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र बचाने के लिए जेल जाएंगे।

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह निडर होकर बोलते रहे हैं। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, आर्थिक मुद्दों, राजनीतिक मुद्दों पर बिना किसी डर के बात की है और स्पष्ट रूप से वह इसके लिए कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आवाज को दबाना आसान नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसी चीज जो कानून में गलत है उसका सही रूप से अवलोकन किया जाएगा और हमें कनविक्शन स्टे जल्द से जल्द मिलेगा।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई बरकरार रहेगी। हम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी कोई धमकी से डरने वाले नहीं हैं...प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं इसलिए वो बार-बार राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के नेताओं को डराते रहते हैं और धमकियां देते रहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में हालात बहुत गंभीर है अगर देशवासी नहीं समझे तो सबको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी घबराने वाले नहीं है। वे सत्य को ईश्वर मानते हैं। एक महीने का जब स्टे कर दिया गया था तो क्या ये इतंजार नहीं कर सकते थे, इतनी क्या जल्दी थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैं इस फैसले और जिस जल्दबाजी से इसे किया गया उससे स्तब्ध हूं। जब एक अपील प्रक्रिया में है तो इस अयोग्यता को लागू करने के तर्क को मैं नहीं समझ पाया। यह भारतीय लोकतंत्र की स्थिति के बारे में दुनिया को एक बहुत ही खराब संकेत भेज रहा है।

भाजपा का पलटवार

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि क्या एक पूरे समाज को चोर बोल सकते हैं? क्या कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए छोटे समाज और ओबीसी समाज का अपमान करना और माफी भी न मांगना ही अभिव्यक्ति की आज़ादी है। गाली देने में और आलोचना करने में अंतर है। वे ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें सजा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो जैसे करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है, राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम अब उन्हें भोगना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और एक विशेष परिवार चाहता है कि उनके लिए अलग कानून बने, उन्हें सज़ा न हो लेकिन मैं उन्हें याद दिला दूं देश 75 साल से प्रजातंत्र अपना चुका है।

राहुल कई मामालों में ज़मानत पर हैं

राहुल पर मानहानि से जुड़े करीब 6 मामले अभी भी चल रहे हैं। अधिकांश केसों की सुनवाई गुजरात की अदालतों में चल रही है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। राहुल गांधी नैशनल हेरल्ड केस में जमानत पर हैं। इसमें 2015 में सोनिया गांधी को को भी जमानत मिली है। 2019 में राहुल गांधी को अहमदाबाद की अदालत ने मानहानि के मामले में जमानत दी थी। यह मामला अहमदाबाद को-ऑपरेटिव बैंक ने दायर किया था। एक आरएसएस वर्कर की ओर से दायर मामले में साल 2019 में मुंबई की अदालत ने मानहानि के मामले में जमानत दी है। महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने आरएसएस वर्कर की ओर दायर केस पर नवंबर 2016 में जमानत दी है। गुवाहाटी कोर्ट ने सितंबर 2016 में राहुल को आरएसएस की ओर से दायर केस में बेल दी है। यह मामला साल 2015 का है। नवंबर 2022 में सावरकर को लेकर राहुल के बयान पर ठाणे में पुलिस ने केस दर्ज किया है।

लिली थॉमस मामले की वजह से सदस्यता तत्काल समाप्त

सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि वह अपनी सजा के दिन 23 मार्च से सदन से अयोग्य हैं। राहुल गांधी को अब एक उच्च न्यायालय का रुख करना होगा और अपनी सजा पर स्टे लेकर आना होगा। 23 मार्च को राहुल गांधी को मोदी उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत ने दोषी ठहराया और दो साल की जेल की सजा सुनाई। सजा ने एक विधायक के रूप में उनकी अयोग्यता की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। राहुल गांधी की अयोग्यता के लिए अपने आदेश में, लोकसभा ने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी सजा की तारीख, यानी 23 मार्च, 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हैं। इसके अलावा, नोटिस में कहा गया है कि यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पढ़ा गया था।

लिली थॉमस केस बना नजीर : एक सीनियर वकील लिली थॉमस ने केंद्र सरकार के खिलाफ इतने मामले लड़े कि उनका उपनाम ही लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पड़ गया था। लिली थॉमस का जन्म कोट्टयम में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई के बाद मद्रास विश्वविद्यालय से एलएलएम की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। 1964 में वो सबसे पहले चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम का विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। थॉमस ने 2003 में जनप्रतिनिधित्व कानून 1952 को चुनौती दी थी। थॉमस लिली ने संविधान के सेक्शन 8(4) को असंवैधानिक दिए जाने का मामला उठाया था। इसी सेक्शन में ये प्रावधान किया गया था कि दोषी करार दिए जाने के बावजूद जनप्रतिनिधि की सदस्यता बनी रहेगी। यदि वो अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देते हैं और वहां से सजा पर रोक लगा दी जाती है तो। हालांकि कोर्ट की तरफ से उनकी याचिका स्वीकार नहीं की गई।

इन दिनों

✍ नीरज कुमार दुबे

राहुल गांधी को सजा अदालत ने सुनाई है

राहुल गांधी को दोषी मानते हुए उनके संसद में सदस्यता खत्म कर दी गई है। क्या आपने कभी देखा है कि अदालत अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में दोषी पाते हुए उसे सजा सुना दे तो दोषी व्यक्ति या उसका समुदाय सड़कों पर हंगामा करने लगे, क्या आपने कभी देखा है कि यदि कोई जाँच एजेंसी या पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाये या जाँच एजेंसी किसी के पास पूछताछ के लिए जाये तो वह व्यक्ति या उसका परिवार सड़क पर हंगामा करने लगता है? नहीं ना। जब देश का आम व्यक्ति कानून का पालन करता है। नोटिस मिलने पर जांच एजेंसी के समक्ष हाजिर होता है। सजा सुनाये जाने पर जेल जाता है या उस फैसले को चुनौती देता है तो वीआईपी व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं करता? देश में दशकों तक राज करने वाले गांधी परिवार के राजनीतिक वारिस राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में अदालत ने सजा सुनाई तो कांग्रेस देशभर में सड़कों पर हंगामा कर रही है। कांग्रेस को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि सजा मोदी सरकार ने नहीं सूरत की एक कोर्ट ने सुनाई है। यही नहीं, जब नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट जाना पड़ा था तब भी कांग्रेस ने ड्रामा कर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह समेत पार्टी के आला नेताओं का सड़कों पर मार्च करा दिया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो कांग्रेसियों ने सड़कों पर जमकर हंगामा काटा। आज जिस तरह से कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेता मार्च निकालते हुए विजय चौक तक पहुँचे और राष्ट्रपति से मुलाकात तथा आगामी विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों का ऐलान करते हुए मोदी सरकार को कोसा उससे सवाल उठता है कि क्यों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। जब दो साल की सजा सुनाये जाने पर कई अन्य सांसदों और विधायकों को संबंधित सदनों की सदस्यता गंवानी पड़ी तो राहुल गांधी को क्यों छूट मिलनी चाहिए? दूसरी ओर, मोदी उपनाम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को अदालत ने सजा सुनाई तो कांग्रेस ने कह दिया कि हमें पहले से पता था यही होगा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की आवाज दबाने की साजिश हो रही है। क्या कांग्रेस को पता नहीं है कि अदालतों में साजिश नहीं होती बल्कि सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। अभी दो दिन पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी मामले में जो जांच कमेटी बनाई है वह क्लीन चिट कमेटी है। क्या कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है?

प्रमुख समाचार

दक्षिण चीन सागर में फिर भिड़े चीन और अमेरिका, युद्धपोत को खदेड़ने का किया दावा

नई दिल्ली। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। चीन ने दावा किया कि उसने दक्षिण चीन सागर में चीनी जलक्षेत्र से एक अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ा है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को दक्षिण चीन सागर में एक विवादित द्वीप के पास चीन द्वारा दावा किए गए क्षेत्रीय जल में प्रवेश करने वाले अमेरिकी नौसेना की लगातार दूसरे दिन निगरानी करने के बाद अमेरिकी सेना को गंभीर परिणाम की चेतावनी दी। दक्षिण चीन सागर में अन्य द्वीपों के स्वामित्व को लेकर फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ भी चीन का विवाद है। हालांकि चीन के दावे का अमेरिकी नौसेना ने खंडन किया है। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि चीन के दावे में सच्चाई नहीं है और अमेरिकी युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभियान को जारी रखा है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता तान केफेई ने एक बयान में कहा, हम अमेरिका से सख्त मांग करते हैं कि वह इस तरह के भड़काऊ व्यवहार को तुरंत बंद करे।

पुरानी पेंशन योजना की मांग के बीच केंद्र ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध के बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र पेंशन से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए एक समिति का गठन करेगी। वित्त विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पेंशन के इस मुद्दे को देखने के लिए वित्त सचिव के तहत एक समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं। सीतारमण ने कहा कि इकसे तहत एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे आम नागरिकों के संरक्षण के लिए राजकोषीय बुद्धिमत्ता बनाये रखते हुए कर्मचारियों की जरूरत पर ध्यान दिया जाए।' यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अनेक गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बदलने का फैसला किया है और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे हैं।

गोल्डी बराड़ के खिलाफ आतंकी सांठगांठ मामले में चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खिलाफ प्रतिबंधित समर्थक खालिस्तान संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) और अन्य समान आतंकवादी समूहों के साथ तीन आतंकवादी-अपराधी सांठगांठ के मामलों में से एक में आरोप पत्र दाखिल किया है। चार्जशीट में 12 अन्य व्यक्तियों को भी नामजद किया गया है। एनआईए ने आरोप लगाया है कि बिश्नोई कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर जेलों से अपने आतंक-अपराध सिंडिकेट का संचालन कर रहा है। वह 2015 से जेल में है। 2022 में जांच एजेंसी ने बिश्नोई को देश में सनसनीखेज अपराधों को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों और आपराधिक सिंडिकेट की साजिश से जुड़े एक मामले में उच्च सुरक्षा वाली भटिंफा केंद्रीय जेल से अपनी हिरासत में लिया था। जांच में बिश्नोई को भारत और विदेशों में विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा रची जा रही कई साजिशों का मुख्य मास्टरमाइंड पाया गया।

ड्रग्स देश की सुरक्षा और भविष्य का दुश्मन है, कर्नाटक में बोले अमित शाह

नई दिल्ली। सहकार समृद्धि सौध के शिलान्यास समारोह और सहकारिता विभाग (कर्नाटक) के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज इस सम्मेलन के दौरान 8 विभिन्न स्थानों पर 1,235 करोड़ रुपये मूल्य की 9,298 किलोग्राम ड्रग्स नष्ट की गई। पिछले नौ माह में 5.94 लाख किलोग्राम नशीला पदार्थ नष्ट किया गया। यह नशा मुक्त भारत हासिल करने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी ने एमएचए अमृत काल में नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है जैसा कि पीएम ने कल्पना की थी। दक्षिणी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आज आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए गहन विचार-विमर्श किया। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई सिर्फ किसी एक सरकार की लड़ाई नहीं जन-जन की लड़ाई है। ड्रग्स देश की सुरक्षा और भविष्य का दुश्मन है।

कनाडा की संसद में उठा अमृतपाल सिंह का मुद्दा, भारत ने दिया ये जवाब

चंडीगढ़। पंजाब का मामला कनाडा की संसद में उठा। कनाडा के एफएम मेलानी जोली ने कहा कि हम पंजाब की विकसित स्थिति से अवगत हैं, इसका बहुत बारीकी से अनुसरण कर रहे हैं। हम अधिक स्थिर स्थिति में लौटने की आशा करते हैं। कनाडा के सांसद इकविंदर गहीर द्वारा मामला उठाए जाने के मामले के जवाब में कनाडा एफएम ने जवाब दिया। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि हम पंजाब की स्थिति से अवगत हैं और हम बहुत बारीकी से इस पर नजर रख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि स्थिति बेहतर होगी। हम समुदाय (सिख समुदाय) के कई सदस्यों की चिंताओं को दूर करना जारी रखेंगे, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने लंदन में हमारे उच्चायोग के बाहर जो कुछ हुआ, उस पर प्रासंगिक एजेंसियों के साथ घटना की रिपोर्ट साझा की है। अब यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर निर्भर है कि वे इसके बारे में क्या कर सकते हैं।

दोराहे पर विपक्ष और चौराहे पर विपक्षी एकता, केंद्र में राहुल

नीरजा चौधरी

गुरुवार को जब मैं यह आलेख लिख रही हूं कि कैसे %भारत जोड़ो यात्रा% के बाद मजबूत होते दिख रहे राहुल गांधी को कुछ विपक्षी दल संदेह से देख रहे हैं, नेहरू-गांधी परिवार के इस महत्वपूर्ण सदस्य को 2019 के उनके मोदी सरनेम को चोर से जोड़ने वाले बयान से संबंधित एक आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की एक अदालत ने दोषी ठहराया है। मैं इस पर बाद में आऊंगी।

भारतीय राजनीति का यह विरोधाभास है कि मजबूत राहुल भाजपा के लिए अच्छी खबर है और विपक्ष के लिए खराब खबर। अच्छी खबर इसलिए, क्योंकि 2024 के चुनाव के मोदी बनाम राहुल बनने की संभावना है और आज जैसे हालात हैं, उसमें लगता है कि इससे मोदी को लाभ होगा। पूरे देश में 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा ने राहुल का कद बढ़ाया है और यह उनकी अपनी उपलब्धि है, जिसमें परिवार के नाम का कोई योगदान नहीं है। और इसीलिए उन्हें मोदी के मुख्य विरोधी की तरह देखा जाने लगा और वह विपक्ष का चेहरा बनते भी दिखे, फिर चाहे विपक्षी दल उन्हें इस रूप में स्वीकार करें या न करें।

विपक्ष की ओर से नेता कौन होगा, इसका फैसला तो 2024 के चुनावों के बाद ही होगा और यह स्थिति भी तब आएगी, जब विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में हो, पर अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। लिहाजा, मोदी बनाम विपक्ष से कौन? यह बहस भाजपा के कथानक को मदद करती है, न कि विपक्ष के एजेंडा को।

आज विपक्ष दो खेमों में बंटा हुआ है और उनके मतभेद इस मुद्दे के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। कुछ ऐसी पार्टियां हैं, जिनका अपने राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन है और वे कांग्रेस को नेतृत्व की भूमिका देने पर राजी हो सकती हैं।

इनमें द्रमुक (तमिलनाडु), झारखंड मुक्ति मोर्चा (झारखंड), राजद और जनता दल (यू) (बिहार), एनसीपी और शिव सेना (महाराष्ट्र) शामिल हैं।

हाल ही में त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली लेफ्ट पार्टियां गैर-भाजपा गठबंधन का समर्थन करेंगी, फिर कांग्रेस उसका नेतृत्व करे या न करे। इन दलों के अलावा ऐसी पार्टियां और नेता भी हैं, जो अपनी सरकार चलाने के लिए कांग्रेस पर निर्भर नहीं हैं, जिनमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (पश्चिम बंगाल), अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (दिल्ली और पंजाब), के चंद्रशेखर राव की बीआरएस (तेलंगाना) शामिल हैं—और ये कांग्रेस (राहुल) का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगी। यहां तक कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और 2024 में गांधी-नेहरू परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी से भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ये वे सीटें हैं, जहां सपा ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर अतीत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चुनाव जीतने में मदद की है।

पिछले हफ्ते ममता बनर्जी ने गौतम अदाणी की प्रधानमंत्री मोदी से कथित करीबी की जेपीसी जांच की कांग्रेस की मांग से प्रत्यक्ष रूप से खुद को दूर रखा था। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति, जो कि कांग्रेस की %बड़े भाई% की भूमिका को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, कुछ अन्य पार्टियों की तरह कांग्रेस की कीमत पर ही आगे बढ़ी हैं। ये पार्टियां जानती हैं कि कांग्रेस के पुनर्जीवन की कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। लिहाजा यह सिर्फ अहंकार का मामला नहीं है, यह संकट इन क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकता है।

विपक्ष में गतिरोध टूटने का एक ही तरीका हो सकता है कि राहुल पीछे हट जाएं और विपक्षी एकता का मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन ऐसा कहना आसान है, करना कठिन। यह कांग्रेस के नए जुड़े समर्थकों को हताश करने जैसा होगा, जिन्होंने भले ही अभी यह तय न किया हो कि वे किसे वोट देंगे, लेकिन राहुल को नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं।

क्षेत्रीय दल अभी अपनी स्थिति को तौल ही रहे थे कि राहुल को दोषी ठहराने वाला फैसला आ गया। सूरत की अदालत के राहुल को दोषी ठहराने वाले फैसले के कुछ मिनट बाद ही राहुल के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण समर्थन आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जताया, जबकि उन्हें विपक्ष की किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी के तौर पर देखा जाता है। यह अतीत से आगे बढ़ने का भी संकेत है; जबकि दिल्ली और पंजाब में आप को सफलता मिली ही कांग्रेस की कीमत पर है।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जब शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, तब कांग्रेस उनके बचाव में सामने नहीं आई थी। अपने दो लेफ्टिनेंट-सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल में होने और केंद्र तथा उपराज्यपाल के साथ हर कदम पर टकराव होने के कारण केजरीवाल अलग-थलग पड़ गए हैं। यहां तक कि उनके लिए दिल्ली का बजट पारित करवाना भी मुश्किल हो गया।

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा का मुख्यमंत्री आज करेंगे वर्चुअल शुभारंभ

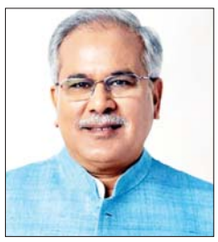

सूरजपुर। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा 25 मार्च को करेंगे। कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क से संबंधित कार्यों की सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि जिले के प्रत्येक विकासखण्डों में 2-2 सहित जिले में कुल 12 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 25 मार्च को सूरजपुर ब्लॉक की केशवनगर गौठान एवं प्रतापपुर ब्लॉक के खंडगवा कला गौठान में रीपा अंतर्गत बनाए गए विभिन्न गतिविधियों के वर्किंग शेड का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी सुराजी ग्राम योजना अंतर्गत एनजीजीबी कार्यक्रम के तहत निर्मित गोठान के तीन चरण हैं। प्रथम चरण में गोठान को पशु संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, द्वितीय चरण में वर्मी कंपोस्ट और अन्य संबंधित उत्पादन केंद्र बनाया गया है एवं तृतीय चरण में गोठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिले में प्रत्येक विसकासखंड दो रीपा के मद से कुल बारह रीपा का निर्माण किया जा रहा है। शासन से इस हेतु प्रति रीपा 2 करोड़ के मान से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस राशि से अधोसंरचना विकास, प्लांट एवं मशीनरी, सीड केपिटल, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, प्रचार-प्रसार एवं ब्रांड प्रमोशन, उत्पाद विक्रय हेतु मार्केटिंग, लाजिस्टिक एवं सप्लाई चेन विकसित करने एवं तकनीकी सहायता एजेसी की सेवाएँ लेने पर खर्च किया जाना है। जिससे ग्रामीण बेरोजगारों, समूह सदस्यों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों स्व रोजगार से जोडने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री की घोषणा से किसानों में खुशी की लहर, कर रहे धन्यवाद, अब मिलेगा ज्यादा फायदा

कोरिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा की है। घोषणा के बाद से किसानों में खुशी की लहर है। इस फैसले का स्वागत करते हुए किसानों का कहना है कि अब वे अधिक धान बेच सकेंगे जिससे लाभ भी अधिक होगा। कोरिया जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के जामपारा के किसान कृष्ण रजवाड़े ने घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्होंने पिछले सीजन में 28 क्विंटल धान की बिक्री की है और अभी अपने खेत में टमाटर, गोभी भी उगा रहे हैं। उन्हें पहले ही धान बेचकर काफी फायदा हुआ है, अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदी से ज्यादा धान बेच सकेंगे। पोत्रीडांड के किसान कोलेश्वर सिंह बताते हैं कि उन्होंने इस वर्ष 42 क्विंटल धान बेचा है। मुख्यमंत्री द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 20 क्विंटल किए जाने से अब उन्हें अतिरिक्त धान को बेचने की चिंता नहीं रहेगी।

ग्राम ओडगी के किसान तेजप्रकाश राजवाड़े बताते हैं कि वे 2.5 एकड़ में धान बोते हैं, पिछली बिक्री 15 क्विंटल की हुई थी। उन्हें और उनके परिवार को जैसे ही इस घोषणा के बारे में पता चला सभी बहुत खुश हुए, क्योंकि इससे हमारे जैसे किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा। इस घोषणा के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि विधानसभा में चर्चा के बाद विनियोग विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान हैं। सम्पूर्ण विश्व आज खाद्य संकट की अग्रसर हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कृषि का अलाभप्रद होना।

हनोदा के यसवंत आस पड़ोस युवा संसद में शामिल हुए

दुर्ग। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार संबद्धता नेहरू युवा केन्द्र राजनांदगांव में जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन नितिन शर्मा(जिला युवा अधिकारी दुर्ग,बेमेतरा,राजनांदगांव)के मार्गदर्शन में गांधी सभागृह नगर पालिका निगम राजनांदगांव में सम्पन्न हुआ।जिसमे राजनांदगांव के 400 युवाओं सहित दुर्ग जिले के युवा जन कल्याण संगठन हनोदा,शौर्य युवा संगठन कोड़िया व कर्मवीर युवा संगठन कातरो सहित एम.एस.डब्लू अंडा के सदस्य शामिल हुवे।कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य युवाओं को संसद में चलने वाली गतिविधियों से अवगत कराना था।जिसके लिए कार्यक्रम स्थल में संसद जैसा माहौल बनाया गया था।जिसमे एक तरफसत्ता पक्ष व दूसरी ओर विपक्ष के बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी। भारत सरकार द्वारा दिये गए मुख्य तीन बिंदु जिसमे जी20 में अध्यक्षता का महत्व,अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष2023 एवं जलवायु परिवर्तन पर युवाओं ने अपनी अपनी बात रखते हुए विषयो पर प्रकाश डाला। जिमसें युवा जन कल्याण संगठन हनोदा के प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रमुख यशवंत साहू ने संसद की अध्यक्षता कर सभी मंत्रियों का स्वागत कर संसद की कार्यवाही को प्रारंभ करवाया। जिसमे रविश साहू ने सत्तापक्ष की ओर से मिलेट्स के फायदे गिनाए,वही विपक्ष के तीखे सवालों के जवाब देते हुए अजय ढिडे ने मिलेट्स को धरातल पर उतार कर सरकारी स्कूलों व आंगनबाड़ी के जरिये सभी बच्चों तक मिलेट्स पहुँचाने की बात कही।कोड़िया के ईशु साहू ने आंकड़े गिना कर सभी को वृस्तृत जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्रीकांत पाण्डेय राज्य निदेशक ने.यू.के छत्तीसगढ़ ने उपस्थित युवाओं को नेहरू युवा केंद्र के कार्यो से अवगत कराते हुए बताया कि अभी दो बड़े आयोजन आस पड़ोस युवा संसद एवं युवा संवाद के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा ।जिसमे बहुत सफलता प्राप्त हुई है।हम आने वाले कुछ दिनों में अपना देश,अपनी माटी अभियान के माध्यम से नेहरू युवा केन्द्र से जुड़े हज़ार संगठनों के माध्यम से नए युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे जिसके लिए प्रत्येक संगठन से एक एक युवाओं को दिल्ली ले जाकर ट्रेनिग देंगे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतोष पाण्डेय(सांसद राजनांदगांव) थे।अध्यक्षता पद्मश्री पुखराज बाफ्ना ने की।विशेष अतिथि जितेंद्र सोनी(मास्टर ट्रेनर व सलहकार ने.यू.के.दुर्ग) सहित दुर्ग के एनवायवी यादवेंद्र साहू, प्रकाश पटेल,भूपेंद्र कुम्भकार, राकेश साहू, आदित्य भारद्वाज, रोशन पटेल, राहुल चंद्रकार, नरेश साहू, कुणाल कोसरे, राजा पटेल, खूब साहू, विनय साहू, राजा टंडन, दादू यादव, राज यादव, उपस्थित थे।

भाजपा की बोरी लिटिया मंडल की कार्यकारिणी घोषित

दुर्ग। भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग के अध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा के अनुमोदन एवं जिला संगठन प्रभारी श्री राजीव अग्रवाल की सहमति से बोरी लिटिया मंडल अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की।

अध्यक्ष- कृष्णा पटेल, उपाध्यक्ष- संजय कश्यप, वीरेंद्र सोनी, सीताराम पटेल, श्रीमती रेखा सेन, महामंत्री- डॉ. जोहन वर्मा, भोमराज जैन, मंत्री- मोतीराम वर्मा, श्यामू पारकर, लल्ला साहू, चुममन साहू, सूरज देशमुख, कोषाध्यक्ष- मनीष साहू, सह कोषाध्यक्ष- राजेंद्र पटेल, मीडिया प्रभारी- कृष्णा साहू, सहमीडिया प्रभारी- प्रभु उमरे।

कार्यकारिणी सदस्य:- अरविंद पटेल, श्रीमती धनेश्वरी वर्मा, श्रीमती कमला डौडे, श्रीमती उर्वशी पटेल, श्रीमती सत्यभामा वर्मा, श्रीमती पूनम पटेल, रूपलाल निषाद, भंवरलाल बमभोले, जितेंद्र देशमुख, जलेश्वर वर्मा, रतन वर्मा, भारतभूषण राजपूत, परमेश्वर वर्मा, केशव पटेल, तुकाराम देशमुख, हेमसिंह वर्मा, तुलेश्वर पटेल, शीतल ठाकुर, उत्तम साहू, रघुनंदन वर्मा, नारायण चतुर्वेदी, गिरवर पटेल, विजय सेन, नरेंद्र दिललीवार, पूनऊ साहू, सुरेश निषाद, चुमन साहू, ज्ञानेश्वर हरमुख, सुदामा निषाद, बुधराम साहू, रूपलाल निषाद, देवलाल दिल्लीवार ।

स्थायी आमंत्रित सदस्य:- विजय बघेल, सुश्री सरोज पाण्डेय, जितेन्द्र वर्मा, लाभचंद बाफना, जितेंद्र साहू, पवन शर्मा, बोधन यादव, रमेश पटेल, श्रीमती सुनीता डहरिया, अजय उमरे, प्रशांत वर्मा, डॉ रघुनंदन वर्मा, भगत वर्मा, टीकम पटेल, श्रवण देशमुख, रमेश देशमुख।

विशेष आमंत्रित सदस्य:- राजेश कांत जोशी, हेमचंद जैन, प्रशांत वर्मा, पिरीत राम साहू, गन्नू साहू ,भोला महाराज, शीतल ठाकुर, इंद्र कुमार ताम्रकार, गणेश साहू, रामखिलावन देवांगन, युवराज पटेल, गैंद सिंह वर्मा, हीरा लाल वर्मा, दाऊ अवध राम पटेल, सेवा राम साहू, श्रीमती चारुलता हरमुख, श्रीमती सुमन देशमुख, अर्जुन पटेल, भीषम पटेल, हेमंत दिल्लीवार, विजय धनकर, विजय कुमार सेन ,महावीर पटेल ,मुरली देवांगन ,धन सिंह वर्मा, विशेश्वर वर्मा, भीखम पटेल, उत्तम साहू, एन कुमार साहू, सुशील बंजारे, तुलेश्वर पटेल, केदार वर्मा, संतोष साहू ,टेमन साहू, नरेंद्र दिललीवार, श्रीमती सुभद्रा धनकर, सुरेश पटेल, प्रहलाद वर्मा, उत्तम साहू, तुकाराम देशमुख, नरसिंह पटेल, रमेश पटेल, दुखित राम पटेल, मनोज चतुर्वेदी, दयालाल टंडन, भागबली मारकंडे, हेमंत गुप्ता।

झाड़-फूंक के चक्कर में गंवा बैठा पैर

कोरबा। पैर में हुए सूजन के उपचार में लापरवाही बरतना एक ग्रामीण को काफी महंगा पड़ गया है। संक्रमण फैलने के कारण उसके पैर को काटने की नौबत आ गई है। ग्राम चाकामार में रहने वाला ग्रामीण अस्पताल में उपचार कराने के बजाए बैगा से झाड़फूंक कराता रहा, जिसके कारण यह नौबत आ गई। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सस्ता उपचार सुलभ हो सके इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा गांव-गांव में अस्पताल खोल दिया गया है। बावजूद इसके लोग आज भी अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और झांड़-फूंक के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा ही कुछ कोरबा के ग्राम चाकामार में देखने को मिला है। जहां पैर में हुए सूजन का अस्पताल में उपचार कराने के बजाय बैगा से झाड़-फूंक कराता रह गया। जिसका नतीजा यह हुआ, कि ग्रामीण के पैर में संक्रमण हो गया और चिकित्सक ने उसका एक पैर काटने तक की बात कह डाली।

नगर पंचायत उतई में हाथ जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन सम्पन्न

दुर्ग। नगर पंचायत उतई में हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ सर्वप्रथम वार्ड क्रमांक 1 इंदिरा नगर से यात्रा शुरू हुई और वार्ड क्रमांक 2 वार्ड क्रमांक 9 और वार्ड क्रमांक 3 में जाकर प्रथम दिवस हाथ जोड़ यात्रा संपन्न हुई। हाथ जोड़ यात्रा को सफल बनाने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र साहू जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शालिनी यादव जनपद अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख नगर पंचायत अध्यक्ष डिकेंद्र हिरवानी जनपद पंचायत उपाध्यक्ष झमित गायकवाड सहकारी समिति उतई के अध्यक्ष दिवाकर गायकवाड वरिष्ठ कांग्रेसी भीष्म हिरवानी नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बहादुर सिंह सभापति राकेश हीरवानी योगिता चंद्राकर पार्षद प्रहलाद वर्मा तोशन साहू राकेश साहू वीरेंद्र गोस्वामी सूरता सिंह एल्डरमैन प्रेम नारायण साहू नगर के कांग्रेस कार्यकर्ता संतोष मानिकपुरी धनंजय नेताम तुकेश्वर ठाकुर कैलाश देवांगन शुभम बमभोले योगेश मांडले सरपंच दिलीप साहू महिला कांग्रेस से राधिका हिरवानी मंजू विरमानी कुमारी बाई एवं अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मरौदा में हाथ से हाथ जोड़ों अभियान

रिसाली। नगर पॉलिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमाक 20 स्टेशन मरोदा में हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा का गुरूवार को समापन हो गया।इस अवसर पर यात्रा प्रभारी सरिता जितेन्द्र साहू के सयोजन में वार्ड में घूम घूमकर सरकार की विभिन्न योजनाओ की जानकारी दी गई। इस अवसर पर रिसाली महापौर श्रीमती शशि अशोक सिन्हा, सभापति केशव बंछोर, यात्रा प्रभारी श्रीमती सरिता जितेंद्र साहू, ब्लाक अध्यक्ष मुकुंद भाउ सहित नगर पॉलिक निगम रिसाली के पार्षद ,एल्डरमेन कॉग्रेस नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

महका कला, परेवाडीह, देउरझाल में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान

पाटन। पाटन विधानसभा के ग्राम ग्राम महकाकला ,परेवाडीह ,देउरझाल में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान सम्पन्न हुआ। जिसमे यात्रा प्रभारी अस्वनी साहू, जवाहर वर्मा, महेंद्र वर्मा, खिलेस बबलू मार्कण्डे राधे स्याम वर्मा सहित अन्य कॉग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए।

परमेश्वरी मंदिर प्रगति नगर में 108 ज्योति कलश प्रज्वलित हुए

रिसाली। प्रगति नगर रिसाली स्थित परमेश्वरी मंदिर प्रगति नगर रिसाली में चैत्र नवरात्रि पर 108 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित किए गए हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन पूजन अर्चन कर ज्योति कलश की स्थापना की गई। देवांगन जन कल्याण समिति भिलाई के अध्यक्ष घनश्याम कुमार देवांगन व उनकी पत्नी सुमन देवांगन ने नवरात्रि पूजा में मुख्य यजमान के रूप में पूजन कार्य मे शामिल हुए। पूजा के पश्चात श्रद्धालुओं को भोग-प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से देवांगन जन कल्याण समिति के सचिव विनोद देवांगन, गजेन्द्र देवांगन, राधेश्याम देवांगन, राजू देवांगन, श्रवण देवांगन, अनंत देवांगन, रामानंद देवांगन, हेमकैलाश देवांगन, शांति लाल देवांगन, रेशमलाल देवांगन, खुमानसिंह देवांगन, चूरनलाल देवांगन, झनक देवांगन, राजेन्द्र लिमजे, रामगोपाल देवांगन, चंदू देवांगन महेंद्र देवांगन, सुमन देवांगन, कल्पना देवांगन, जयश्री देवांगन, दामिनी, मधुबाला, कांति देवांगन उपस्थित थे। गुरूवार को परमेश्वरी मंदिर का 14 वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को दीपों से सजाया गया था। परमेश्वरी मंदिर में नवरात्रि पर्व में प्रतिदिन संध्या में महिला प्रकोष्ठ एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा जसगीत एवं भक्ति संगीत का आयोजन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

तनेरा के ग्रामीणों को नहीं मिल रहा नियमित राशन

कोरबा। पोड़ी-उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत तनेरा के अधिकांश ग्रामीणों को यहां के उचित मूल्य की दुकान से राशन नहीं मिल रहा है। इन हितग्राहियों ने रजिस्टर पर अंगूठा लगाना भी बताया। राशन वितरण में गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हुए जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। राशन कार्डधारी परिवारों को राज्य शासन उचित दर पर सोसायटी के माध्यम से चावल समेत अन्य राशन सामान उपलब्ध कराती है। तनेरा की रामवती, शिवकुंवर, लक्ष्मनिया बाई व पार्वती ने बताया कि हर महीने उनसे रजिस्टर पर अंगूठा लगवाया जाता है। मगर राशन नहीं दिया जा रहा है। इससे शासन वितरण में गड़बड़ी की पूरी आशंका है। ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव पर बंदरबाट का भी आरोप लगाया। इस पर सरपंच अशोक सिंह मरपच्ची का कहना है कि दो-तीन महीने से सोसायटी को 40 से 50 क्विंटल कम राशन का भंडारण किया जा रहा है। इससे अधिकांश हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराने में परेशानी आ रही है। पोड़ी-उपरोड़ा एसडीएम को इसकी जानकारी दी है।

अमरकंटक को जोड़ने वाली पुलिया बारिश में धंसी

गौरेला पेंड्रा मरवाही। बारिश के चलते पकरिया दुर्गा धारा से अमरकंटक को जोड़ने वाली सड़क पर बनी पुलिया धराशायी हो गई है। आरोप है कि पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क में घटिया सामग्री का इस्तमाल किया गया। जिसके चलते ही पुलिस समय से पहले ही धंस गई। पुलिया ढहने के चलते इस मार्ग से अमरकंटक को जाने वाले लोगो को बड़े हादसे की चिंता सताने लगी है तो अधिकरियो बड़े हादसे का इंतजार कर रहे है। पीएमजीएसवाई के तहत गौरेला से पकरिया दुर्गा धारा होकर मध्यप्रदेश के तीर्थ स्थली अमरकंटक को जोड़ने वाली सड़क मार्ग को ठेकेदार द्वारा पिछले दिनों भरे बरसात में रात में बनाया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 5.50 करोड़ की लागत से बनाई गई इस सड़क निर्माण की निगरानी भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियो ने नहीं की जिसके कारण ठेका कंपनी डीसी कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में मनमानी एवं लीपापोती करते हुए घटिया निर्माण करा दिया। जिसके बाद यह सड़क 15 दिनों में ही उखड़ने लगी।

प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी से किसान होंगे सशक्त

जगदलपुर। संसदीय सचिव तथा जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होने इसे किसानों की सशक्तिकरण की दिशा में कांग्रेस सरकार के द्वारा लिया गया ऐतिहासिक निर्णय बताया है। अब तक राज्य में किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही थी। गुरुवार को राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की थी। श्री जैन ने कहा है कि सीएम श्री भूपेश बघेल इससे पूर्व आगामी सत्र से 2800 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य घोषित किया था। इन दोनों फैसलों के लिए जगदलपुर विधायक ने क्षेत्र के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होने कहा है कि यह फैसले बताते हैं कि राज्य के किसानों का सशक्तिकरण श्री बघेल की प्राथमिकताओ में से एक है।

30 जून तक जिला दुर्ग जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया

दुर्ग। जिला दुर्ग में गर्मी के मौसम पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा दुर्ग जिले को 30 जून तक जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया है। तय तिथि 30 जून तक सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय/अर्ध शासकीय/नगरी निकायों को पेयजल हेतु अपने क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु निर्धारित नियमों का पालन भी उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/नगरी निकाय/ तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। दुर्ग संपूर्ण नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

भूकंप के झटके से कोई नुकसान नहीं

अंबिकापुर। संभाग मुख्यालय सरगुजा अंबिकापुर के कुछ इलाको में शुक्रवार सुबह करीब 10.30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घबराकर अपने—अपने घरों से बाहर निकले गए। डर का माहौल भी बना रहा अभी फिलहाल भूकंप के केंद्र और इसकी तीव्रता के बारे में जानकारी नहीं मिली है। सरगुजा बलरामपुर सूरजपुर कोरिया भटगांव इलाके में भूकंप के झटके लगे हैं। 6 से 8 सेंकट ही इसका असर रहा ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इससे काई जान-माल की हानि नहीं हुई है। इसके पूर्व भी 14 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को ही अंबिकापुर संभाग मुख्यालय में सुबह ही भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसका भी केंद्र अंबिकापुर से 65 किमी दूर जमीन से 10 किमी अंदर बताया जा रहा है। नेशनल सेंटर फार सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की गहराई जमीन से 10 किमी नीचे बतायी जा रही है।

खदान के मुहाने पर ढपढप व कसरेंगा के ग्रामीणों ने 3 घंटे दिया धरना

■ पीने के पानी की मांग, काम पर जाने से कर्मचारियों को रोका

कोरबा। एसईसीएल ढेलवाडीह खदान के मुहाने पर गुरुवार सुबह 6 बजे से ढपढप व कसरेंगा के ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन कर दोनों गांवों में पीने के पानी की व्याप्त समस्या के निराकरण की मांग की। पहली शिफ्ट की ड्यूटी पर पहुंचे कर्मचारियों को भी रोक दिया। इसकी जानकारी एसईसीएल उपक्षेत्रीय कार्यालय ढेलवाडीह के अफसरों को होने पर मौके पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। उसके बाद काम पर पहुंचे कर्मचारी माइंस के भीतर कार्यस्थल तक पहुंचे। इधर करीब 3 घंटे तक खदान के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी रहा। कंपनी के दफ्तर में हुई चर्चा के बाद मांगों को पूरी करने सकारात्मक कदम उठाए जाने के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त हुआ। विभिन्न मांगों को

लेकर किए गए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में दोनों गांवों की महिलाएं भी शामिल हुईं।

ढपढप व कसरेंगा के ग्रामीणों की प्रमुख मांगें

पाइप लाइन से घरों में पेयजल की आपूर्ति की जाए। खदान से निकाली जा रही पानी से गांवों के तालाबों को भरा जाए। बिगड़े बोर पंपों का सुधार कार्य कराया जाए। ब्लास्टिंग से ग्रामीणों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। सीसी रोड सड़क का निर्माण कराया जाए।

बताया गया कि दफ्तर में हुई बैठक में चर्चा के दौरान एसईसीएल अफसरों ने दोनों ही गांव में टैंकर से पानी सप्लाई की बात कही तो महिलाओं ने रोजाना समय पर नहीं पहुंचना बताया। प्रभावितों ने कहा कि पहले इसकी कवायद की गई थी। समय पर टैंकर नहीं पहुंचा फिर बाद में टैंकर से पानी आपूर्ति भी बंद हो गई। ऐसे में पाइप के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति की मांग जोर-शोर से रखी।

आश्वासन पर कटघोरा एसडीएम कार्यालय के घेराव आंदोलन स्थगित होने के दो दिन बाद एसईसीएल बलगी खदान से प्रभावित सुराकछार बस्ती के भू.धंसान प्रभावितों की उक्त हल्का नंबर के पटवारी ने जानकारी जुटाई। तीन साल से प्रबंधन की ओर से प्रभावितों को क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने से घेराव की चेतावनी दी थी। बलगी खदान में डिपिलरिंग के दौरान साल 2009 में भू-धंसान की घटना सामने आई थी। इस वजह से खेती-किसानी का कार्य नहीं कर पा रहे किसानों को एसईसीएल प्रबंधन हर साल क्षतिपूर्ति राशि दे रही है।

आज से शुरू होगा 10वीं व 12वीं की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन, एक शिक्षक जांचेगा 40 कॉपी

कवर्धा। बोर्ड परीक्षा अब अंतिम दौर पर है। इस बीच शनिवार 25 मार्च से कक्षा 10वीं व 12वीं के उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन को लेकर माशिमं ने कवर्धा शहर के स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल को मूल्यांकन केन्द्र बनाया है। इस केन्द्र में माशिमं ने 50 हजार उत्तरपुस्तिका भेजी है।

मूल्यांकन केन्द्र से मिली जानकारी अनुसार आज शुक्रवार को मूल्यांकन के संबंध में माशिमं द्वारा वीसी के माध्यम से बैठक होगी। 25 मार्च से मूल्यांकन कार्य शुरू होगी व 17 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य पूर्ण करना है। जिले से 250 से अधिक मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पहले दिन 25 मार्च को सभी मूल्यांकनकर्ता शिक्षक को केवल 5-5 कॉपी दी जाएगी। पहले दिन इन कॉपी का मूल्यांकन किए जाने के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद 40 कॉपी प्रतिदिन मूल्यांकनकर्ता शिक्षक को दिया जाएगा। माशिमं द्वारा मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों को काम के बदले में राशि दिया जाता है।जानकारी अनुसार, इस बार भी कक्षा 10वीं के एक उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन के लिए 10 रुपए व 12वीं के लिए 11 रुपए निर्धारित की गई है। पूर्व वर्ष भी इसी रेट पर मूल्यांकन किया गया था।

मई माह में आएंगे परिणाम: प्रदेश में करीब 15 से अधिक जगहों में मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। सभी जगहों में 17 अप्रैल तक कार्य पूरा किए जाएंगे। ऐसे में मई के पहले या दूसरे हफ्ते तक परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की संभावना है। दूसरी ओर वर्तमान समय में जिले के केवल 12वीं की परीक्षा हो रही है। कक्षा 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई है। जिले में बोर्ड परीक्षा को लेकर माशिमं द्वारा 70 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर विपक्षी दल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। कांग्रेस की अगुवाई में एक दर्जन से अधिक विपक्षी दलों ने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का हवाला देते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक सहित चौदह राजनीतिक दलों ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की और विपक्षी नेताओं की मनमानी गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई और ईडी के लिए गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी के बाद के दिशानिर्देशों की मांग की। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की पीठ ने विपक्षी दलों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया और कहा कि याचिका पर पांच अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। सिंघवी ने कहा, ''95 फीसदी मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। हम गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी के बाद दिशा निर्देशों की मांग कर रहे हैं।'' इस पर पीठ ने कहा, ''हम इस पर 5 अप्रैल को सुनवाई करेंगे।'

राहुल का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है : नड्डा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तथ्यों से परे और मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत है। उन्होंने आगे लिखा, 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल ने राफेल के नाम पर देश को भ्रमित करने की कोशिश की। जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और राहुल गांधी को मनगढ़ंत आरोप के लिए बिना शर्त माफी माँगनी पड़ी थी। फिर चौकीदार चोर है का शोर मचाया। उन्होंने ये भी कहा, राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया। उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार-बार समझाने और माफी माँगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुँचाई।

जेपी नड्डा के आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष ने किया पलटवार

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी पर भाजपा के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के हमले को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने पहले चोरी में सहयोग किया और अब जातिगत राजनीति का प्रयोग कर रही है जो शर्मनाक है। खड़गे ने यह भी कहा कि मोदी सरकार अडानी समूह से जुड़े मामले में जेपीसी गठित करने की मांग से भाग नहीं सकती। उन्होंने ट्वीट किया, 'मोदी सरकार जेपीसी से भाग नहीं सकती! बैंक व जनता के पैसे लेकर नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी भागे! ओबीसी वर्ग तो नहीं भागा, फिर उनका अपमान कैसे हुआ? स्टेट बैंक और एलआईसी को नुकसान आपके परम मित्र ने पहुंचाया!' खड़गे ने कहा, एक तो चोरी में सहयोग, फिर जातिगत राजनीति का प्रयोग! शर्मनाक! पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ठोस राजनीतिक विमर्श लोकतंत्र का सार होता है। लोकतांत्रिक विपक्ष की प्रमुख आवाज को खामोश करने के लिए कानून का उपयोग ऐसे नहीं होना चाहिए।

राहुल ने लोकतंत्र का अपमान किया : किरण रिजिजू

नई दिल्ली। मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद देश की सियासत गर्म हो गई है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जहां, कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश बताया तो भाजपा ने भी पलटवार किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसको लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सभी गांधी उपनाम वालों को केवल इसलिए दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र, सशस्त्र सेना और देश की संस्थानों का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके राहुल पर निशाना साधा। लिखा, हम सभी गांधी उपनाम वालों को दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र, हमारे सशस्त्र बलों और भारतीय संस्थानों का अपमान किया है। राहुल गांधी ने बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की और पूरे ओबीसी समुदाय को अपमानित किया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ कांग्रेस नेता इसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं।

बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी का राहुल पर हमला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर इशारों-इशारों में निशाना साधा है। योगी ने कहा कि देश के बाहर देश को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां एक ओर भारत की प्रगति और विरासत पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है। पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होती है। भारत के लोकतंत्र को दुनिया अलंकार करने के लिए ललायित दिखाई दे रही है। वहीं कुछ लोग हैं जो देश के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं। वहीं राहुल के मोदी सरनेम वाले मामले को लेकर सीएम योगी ने कहा कि एक सांसद को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। गुरुवार को देश ने कांग्रेस के कृत्य को देखा। सीएम ने कहा कि 9 साल में हमने 35 हजार करोड़ की परियोजनाएं काशी और उसके आसपास पूरी की हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं तो काशी के लिए कुछ ना कुछ एक नई सौगात लेकर आते हैं।

निम्न सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की प्रक्रिया पूरी हुई

लोकसभा में हंगामे के बीच वित्त विधेयक पारित

नयी दिल्ली। लोकसभा ने शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सरकार द्वारा लाये गये संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया और इसके साथ आगामी वित्त वर्ष के बजट की प्रक्रिया सदन में पूरी हो गयी। लोकसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू हुई। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कराए। इस बीच कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्य अडाणी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग कर रहे थे और इससे संबंधित नारे लिखी तख्तियों को आसन के समक्ष आकर लहरा रहे थे।

हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 को सदन के विचारार्थ और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। विधेयक को पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि कुछ हितधारकों से सुझाव मिले हैं कि सरकारी

कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार होना चाहिए और इस के लिए वह एक समिति के गठन का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने कहा, ''मैं वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का प्रस्ताव करती हूं जो सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित मुद्दों पर राजकोषीय बुद्धिमत्ता के साथ विचार करेगी।'' सीतारमण ने सदन में यह भी कहा कि विदेशी दौरों के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान 'लिबरलाइज्ड रिमिटेन्स स्कीम' (एलआरएस) के तहत कैप्चर नहीं किये जा रहे हैं और इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक से विचार करने को कहा गया है।

इसके बाद सभा ने क्रमवार वित्त विधेयक से जुड़े सरकारी संशोधनों को मंजूरी दी और यथासंशोधित वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। साथ ही सदन ने वित्त विधेयक पर विपक्षी सदस्यों द्वारा लाये गये संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया।

सदन ने बृहस्पतिवार को 'गिलोटिन' के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों को और संबंधित विनियोग विधेयक को भी हंगामे के बीच ध्वनिमत से मंजूरी दी थी। आज वित्त विधेयक पारित होने के साथ निम्न सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की प्रक्रिया पूरी हो गयी। लोकसभा में एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण द्वारा आम बजट 2023-24 पेश किए जाने के साथ ही बजट प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी।

राहुल को सजा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 14 विपक्षी दल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी गहमा-गहमी वाला है। जहां एक तरफ मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी की वजह से राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई। वहीं सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल के आरोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। बिलकिस बानों केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक बेंच गठित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 20 मार्च से 24 मार्च 2023 तक क्या कुछ हुआ। कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले 14 राजनीतिक दलों द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 5 अप्रैल को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई के मनमाने इस्तेमाल के खिलाफ 14 राजनीतिक दलों द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि याचिका में पूर्व-गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद और उनके प्रवर्तन के लिए दिशानिर्देश मांगे गए हैं।

राहुल को 2 साल की जेल

सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज केस में उन्हें गुरुवार को दो साल जेल की सजा सुनाई। मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट एच. एच. वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके। कांग्रेस इस फैसले को चुनौती देगी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपी संसद सदस्य हैं। जनता के सामने वह जो कुछ भाषण देते हैं, उसका व्यापक असर होता है। अगर कम सजा दी जाती है, तो गलत संदेश जाएगा।

निकाह-हलाला पर नई बेंच

निकाह हलाला और बहुविवाह की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पांच जजों की नई संवैधानिक बेंच का गठन करेगा। चीफ जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ ने कहा, %मैं इस पर विचार करूंगा। उपयुक्त चरण में, मैं एक संविधान पीठ का गठन करूंगा। कई अहम केस संवैधानिक बेंच के सामने लंबित हैं।% याची वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि पहले की संवैधानिक बेंच के दो जज रिटायर हो चुके हैं, नई बेंच बने।

विशेष बेंच गठित करने पर जताई सहमति

सुप्रीम कोर्ट 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक बेंच गठित करने पर सहमत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने अपनी वकील शोभा गुप्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाली बानो को आश्वासन दिया कि नई पीठ का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ओआरओपी के बकाये का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हुए राहुल गांधी

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 'मोदी उपनाम' वाली एक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में सूरत की अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को संसद पहुंचे और लोकसभा की कार्यवाही में भी शामिल हुए। राहुल गांधी संसद भवन में हुई कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल हुए जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उपस्थित थीं। वह लोकसभा की कार्यवाही आरंभ होने के समय सदन में मौजूद थे। पार्टी के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से यह आग्रह किया कि राहुल गांधी को सत्तापक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों पर जवाब देने का मौका दिया जाए। इसकी अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा किया जिससे सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गयी। उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ''मोदी उपनाम'' संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिन तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें।

राहुल को लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था : सुशील मोदी

नयी दिल्ली। राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कांग्रेस नेता को शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाते ही वह बतौर सांसद अयोग्य हो गये थे। लोकसभा में वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी ने शुक्रवार को कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामे के कारण एक घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मोदी ने कहा, ''मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उन्हें (गांधी को) संसद की कार्यवाही में आज हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वह अयोग्य हो चुके हैं।'' मोदी ने कहा कि वह इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों की राय के साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि गांधी की अयोग्यता केवल तभी रोकी जा सकती है, यदि उच्चतम न्यायपालिका उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करती है। उन्होंने कहा कि दोषसिद्धि का निलंबन केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामले में ही होता है। भाजपा नेता ने भी पटना में इसी मामले में गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर कर रखी है।

खेल
प्रमुख समाचार

एशिया कप : भारत किसी अन्य देश में खेलेगी अपने मैच

नई दिल्ली। एशिया कप के इस बार के आयोजन स्थल को लेकर मचा घमासान सुलझता नजर आ रहा है। बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) धीरे-धीरे अपने रूख को नरम करने के मूड में नजर आ रहे हैं ताकि दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में खेल सकें। पहले के कार्यक्रम के अनुसार साल 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में आयोजित होना है। हालांकि, सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए बीसीसीआई ने पाकिस्तान दौरा नहीं करने और एशिया कप किसी और जगह आयोजित कराने की बात रखी थी। इस पर पीसीबी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई थी। अब हालांकि एक नये फॉर्मूल के बारे में विचार किया जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार एशिया कप इस बार पाकिस्तान में ही आयोजित कराया जा सकता है। हालांकि टीम इंडिया टूर्नामेंट में अपने मैच किसी और देश में खेलेगी। टीम इंडिया के मैच कहां खेले जाएंगे, इसे लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है लेकिन यूएई, ओमान, श्रीलंका और यहां तक कि इंग्लैंड के नाम पर विचार जारी है जहां भारत के पांच मैच आयोजित कराए जा सकते हैं। इनमें कम से कम दो मैच ऐसे होंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाएंगे।

एशिया कप में छह टीमें खेलेंगी। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। 50 ओवर के फॉर्मेट में एशिया कप इस बार सितंबर में आयोजिक किया जाना है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका दूसरे ग्रुप में है। कुल 13 मैच एशिया कप में 13 दिन में खेले जाएंगे। इसमें फाइनल में शामिल है। दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर-4 में जाएंगी और फिर दो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल की भी संभावना बरकरार है। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस बात पर जोर देता रहा है कि भारत को सितंबर में होने वाले एशिया कप में खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 398 अंक टूटा निफ्टी 17000 से नीचे

नई दिल्ली। लगातार दूसरे दिन घरेलू शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स बेंचमार्क 398.18 अंक फिसलकर 57,527.10 अंकों के लेवल पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी बेंचमार्क 131.85 अंक टूटकर 16,945.05 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबारी सेशन के दौरान बजाज ट्विन्स के शेयरों में चार प्रतिशत तक की गिरावट आई। बीते एक हफ्ते के दौरान शेयर बाजार में निवेशकों को 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पिछले हफ्ते शुक्रवार को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 257.52 लाख करोड़ रुपए था, वह इस हफ्ते 254.44 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए लॉन्च किया नया एप

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने एआईएस एप लॉन्च कर करदाताओं को एक नई राहत दी है। इस एप का इस्तेमाल कर टैक्सपेयर्स अपने टीडीएस व टीसीएस की विवरणी समेत ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों से जुड़ी सारी जानकारी अपने मोबाइल पर ही देख सकेंगे। साथ ही उन्हें विभाग की सेवाओं पर अपनी राय देने का भी विकल्प मिलेगा। करदाता इस मोबाइल एप के जरिए वार्षिक सूचना विवरण और करदाता सूचना ब्यौरा की जानकारी ले सकेंगे। ये सेवाएं आयकर विभाग की ओर से नि:शुल्क उपलब्ध कराईं जाएंगी। करदाता मोबाइल एप 'AIS for Taxpayers' को गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से इंस्टॉल कर सकेंगे। इस एप को इंस्टॉल करने के बाद करदाताओं को इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए उन्हें अपना पैन नंबर उपलब्ध कराना होगा।

नेक्सा को वाहन उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बनाने का लक्ष्य

नईदिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया अपने नेक्सा खुदरा आउटलेट के जरिए पेश महंगे वाहनों की बिक्री अगले वर्ष तक हुंदै और टाटा मोटर्स के महंगे वाहनों की कुल बिक्री से अधिक करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने यह कहा। मारुति सुजुकी के महंगे वाहनों की बिक्री के लिए नेक्सा की खुदरा श्रृंखला 2015 में शुरू हुई थी। अब इसकी कुल बिक्री 20 लाख इकाई के पार चली गई है। मौजूदा समय में इसके तहत बलेनो, इग्निस, सियाज, एक्सएल6 और ग्रांड विटारा जैसी गाड़ियों की बिक्री होती है। आगामी एसयूवी फ्रॉन्क्स और जिमनी की पेशकश भी इसी श्रृंखला के तहत की जाएगी। कंपनी को उम्मीद है कि 2023-24 में उसके यात्री वाहनों की बिक्री पांच से 7.5 प्रतिशत तक बढ़ेगी। श्रीवास्तव ने कहा, ''नेक्सा में हमने 20 लाख इकाई का आंकड़ा पार कर लिया है।

कच्चा तेल 10 माह में 20 रुपये सस्ता

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं मिल रही है। जून, 2022 से लेकर इस साल मार्च तक यानी 10 महीने में कच्चे तेल की कीमत 58.80 रुपये से घटकर 38.70 रुपये प्रति लीटर रह गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि में पेट्रोल 96.70 रुपये और डीजल 89.60 रुपये लीटर पर स्थिर रहा। वैश्विक बाजार में भी पिछले सप्ताह क्रूड 71 डॉलर बैरल के नीचे आ गया, जो इसका 15 महीने का निचला स्तर है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों को समान रखने के बाद भी तीन प्रमुख तेल कंपनियों को अप्रैल से सितंबर, 2022 के बीच 21,201 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इसकी भरपाई के लिए सरकार ने इस दौरान इन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये की पूंजी भी दी।

कश्मीर में बदलता कारोबारी माहौल और विदेशी निवेश की संभावनाएं

अवधेश कुमार

पिछले दिनों श्रीनगर के सेमपोरा में विदेशी निवेश से निर्मित होने वाले 250 करोड़ रुपये की लागत के एक मॉल की आधारशिला उपरा'यपाल मनोज सिन्हा ने रखी। यह श्रीनगर ही नहीं, विदेशी पूंजी से बनने वाला प्रदेश का पहला मॉल होगा, जिसे 2026 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। दुबई का एम्मार समूह इसका निर्माण कर रहा है। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर में डेढ़ सौ-डेढ़ सौ करोड़ रुपये की लागत वाले एक-एक आईटी टावर का विनिर्माण भी एम्मार समूह कर रहा है। यह इसका प्रमाण है कि अनु'छेद ×70 हटाए जाने के बाद की बदली परिस्थितियों में जम्मू-कश्मीर में भी विदेशी निवेश आ रहा है। उपरा'यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक, नई औद्योगिक नीति आने के 22 महीनों में 5,000 से अधिक देसी व विदेशी कंपनियों के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

यह सच है कि वहां नए उद्योग आरंभ हो रहे हैं। यह प्रदेश के बदलते आर्थिक, वित्तीय व कारोबारी स्थिति का ही प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिलान्यास की गई परियोजनाओं की कुल लागत ×8 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। प्रदेश ने अगले कुछ वर्षों में कुल 75,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। वस्तुत: जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार पूर्व की सभी सरकारों से अलग दृष्टिकोण से काम कर रही है। आर्थिक गतिविधियों द्वारा प्रदेश का माहौल बदलना इनमें प्रमुख है।

हाल ही में इंडिया-यूएई इन्वेस्टर्स मीट में जम्मू कश्मीर की ओर से उपरा'यपाल सिन्हा ने घोषणा की कि निवेश संबंधी प्रस्ताव आने के 15 दिन के अंदर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। देश के किसी भी प्रदेश में ऐसी घोषणा शायद ही हुई हो। भले ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं पूरी तरह बंद नहीं हुई हैं, पर शांति और बेहतर सुरक्षा माहौल को कोई नकार नहीं सकता। आम लोग यह महसूस करने लगे हैं कि पहले की तरह आतंकवादियों के पनपने, उन्हें संरक्षण मिलने तथा हिंसात्मक गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। पिछले वर्ष एक करोड़ 88 लाख पर्यटकों के आने की सूचना है।

अनु'छेद ×70 हटाने के साथ ऐसे अनेक कानूनों का अंत कर दिया गया, जो वहां की स्वाभाविक, आर्थिक व कारोबारी गतिविधियों के रास्ते की बाधाएं थीं। अगर भूमि कानून नहीं बदला होता, तो उपरा'यपाल यह वादा नहीं कर सकते थे कि निवेश घोषणा के 15 दिनों के अंदर जमीन उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि शत-प्रतिशत आधारभूत ढांचा तैयार हो गया है, यह नहीं कहा जा सकता। मगर तीन वर्षों में निवेश के लिए वातावरण तैयार करने में काफी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में कारोबार के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। सामान्य एवं प्रोफेशनल शिक्षा का भी विस्तार हुआ है। अभी तक कृषि और पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मूलाधार रहा है। लेकिन अब कंपनियां पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, रसद, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा, पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र में भी रुचि दिखा रही हैं और निवेश कर रही हैं। स्वाभाविक ही आधारभूत संरचना एवं सरकारी नीतियों का ध्यान इन्हीं पर होगा। भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आज बदलाव का परिदृश्य उत्पन्न कर रहा है। एक लाख करोड़ रुपये की तो हाईवे और उससे जुड़ी अन्य परियोजनाएं चल रही हैं। रेल मार्ग के जरिये कश्मीर को इसी वर्ष कन्याकुमारी से जोड़ने पर तेजी से काम चल रहा है। हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण हुआ है। इन सबसे निवेशकों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है। सरकार के साथ उद्योगपतियों, कारोबारियों का भी दायित्व है कि वे वातावरण बदलने में अपने सक्रिय भूमिका के साथ सहयोग करें।

जनवरी, 2021 में जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने नए निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक विकास को ब्लॉक स्तर तक ले जाने के लिए 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक नई औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की थी, जिसका सकारात्मक असर हुआ। उम्मीद है कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर भी अन्य रा'यों के समानांतर आर्थिक विकास की पटरी पर दौड़ता दिखाई देगा।

अध्यादेश न फाड़ा होता तो आज नहीं आती ये नौबत

अभिनय आकाश

27 सितंबर 2013 को कांग्रेस महासचिव अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो मिनट का ब्रेक डालकर राहुल ने अपनी सरकार के खिलाफ बगावत का ऐसा बिगुल फूंका जिसकी चर्चा राजनीति के इतिहास में हमेशा होती रही है। राहुल ने मनमोहन सरकार के लाए अध्यादेश पर बोलते हुए कहा था कि 'मैं आपको बताता हूं कि इस अध्यादेश पर मेरी निजी राय क्या है? वह सरासर बकवास है। इसे फाड़ के फेंक देना चाहिए। मेरी तो यही राय है।' राहुल के इस तेवर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हैरान हो गए थे। आज से ठीक 10 साल पहले मनमोहन सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को न फाड़ा होता तो उनकी सदस्यता पर संकट के बादल मंडराते नहीं दिखते। सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया। ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं। साल 2013 के सितंबर महीने में यूपीए सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया था। इसका मकसद उसी साल जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को निष्क्रिय करना था। जिसमें अदालत ने कहा था कि दोषी पाए जाने पर सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। कांग्रेस द्वारा इस अध्यादेश को लाए जाने पर बीजेपी, लेफ्ट और कई विपक्षी दलों ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा था। मनमोहन सरकार पर उस वक्त भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे और कहा गया कि इसी मकसद के लिए ये अध्यादेश लाया गया। उसी वक्त आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव पर भी चारा घोटाले को लेकर अयोग्यता की तलवार लटक रही थी। कांग्रेस की ओर से जब वे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका के दौरे पर थे। इस घटना के बाद राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा था। बाद में अक्टूबर महीने में तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस अध्यादेश को वापस ले लिया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, किसी भी सदस्य को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा होने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। व्यक्ति कारावास की अवधि और एक और छह साल के लिए अयोग्य है। लेकिन, अधिनियम में प्रदान किए गए मौजूदा सदस्यों के लिए एक अपवाद है। वर्तमान सदस्यों के लिए एक अपवाद है; उन्हें अपील करने के लिए सजा की तारीख से तीन महीने की अवधि प्रदान की गई है। अधिनियम कहता है कि अपात्रता तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि अपील का फैसला नहीं हो जाता है। एक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए सांसद की अयोग्यता दो मामलों में हो सकती है। सबसे पहले, यदि वह अपराध जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(1) में सूचीबद्ध है। दूसरा, अगर कानून निर्माता को किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है लेकिन दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है। आरपीए की धारा 8(3) में कहा गया है कि अगर किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और दो साल से कम की कैद की सजा नहीं होती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।

राहुल गांधी और विपक्ष के महत्वाकांक्षी नेता

अजय कुमार

अभी राहुल गांधी के लंदन में भारत विरोधी दिए गए बयान पर माफी मांगने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था अब चार साल पुराने मानहानि के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात की सूरत जिला अदालत ने सजा सुना दी है। ये मामला मोदी सरनेम पर की गई विवादित टिप्पणी का है। दरअसल, 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान कहा था,'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम एक ही क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?

राहुल की इस टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। बीजेपी नेता का कहना था कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया। सूरत कोर्ट ने पहले राहुल से पूछा कि क्या वह मांफी मांगेंगे तो उन्होंने कह दिया कि वह मामला माफी मांगने का नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने राहुल को दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुना दी। हालांकि, अदालत से उन्हें जमानत भी मिल गई है। अदालत ने राहुल को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया था, लेकिन उनको ऊपरी अदालत में अपील के लिए जमानत भी दे दी गई।

राहुल को सजा सुनाते ही यह भी तय हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी, राहुल को इस मामले को सियासी जामा नहीं पहनाना होता तो राहुल कोर्ट में माफी मांग कर बच सकते थे, जैसा वह पहले कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया यानी कांग्रेस ने इस फैसले को सियासी मसला बनाने का मन बना लिया है जिसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। इसीलिए गुजरात की सूरत कोर्ट द्वारा जब राहुल गांधी को सजा सुनाई जा रही थी, तब ही कांग्रेसी राहुल के पक्ष में बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल को सजा सुनाए जाने को लेकर प्रियंका वाड्रा सहित पूरी कांग्रेस एक्टिव मूड में आ गई है। राहुल को सजा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रियंका द्वारा कहा जा रहा है कि वह डरने वाले नहीं हैं। यानी अदालत के फैसलों पर से भी कांग्रेस का विश्वास उठता जा रहा है, जो एक गंभीर मसला है। सबसे खास बात यह है कि राहुल को सजा सुनाए जाने के चलते बीजेपी विरोधी वह नेता भी राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं जो हाल फिलहाल तक राहुल गांधी से दूरी बनाकर रखते थे, इसमें अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता शामिल हैं।

खैर, मोदी-राहुल के बीच की रार से किसको फायदा, किसे नुकसान हुआ की बात करें तो इस जंग का बीजेपी ने तो खूब फायदा उठाया, लेकिन कांग्रेस को इसके विपरीत परिणम झेलने पड़े। कांग्रेस इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उसके सांसदों की सख्या दहाई में सिमट कर रह गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्थान पर है। सबसे खास बात यह है कि मोदी-राहुल की जंग में इनकी पार्टियां भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही हैं। दोनों दलों के दिग्गज नेता प्रेस कांफ्रेंस और ट्विट के माध्यम से एक-दूसरे पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं। याद कीजिए आज जिस तरह से राहुल गाँधी, मोदी और अडाणी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं वैसा ही आरोप 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने राफेल विमान खरीद में दलाली और भ्रष्टाचार को लेकर लगाया था और %चौकीदार चोर है' का नारा दिया था। कांग्रेस ने एक तरह से 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी की अगुवाई में %चौकीदार चोर है% के नारे पर ही लड़ा था, लेकिन उसे चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी। अब अडाणी के मामले में आरोप लगाया जा रहा है। इसमें राहुल को कितनी सफलता मिलेगी यह 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। वैसे यहां यह याद दिलाना भी जरूरी है कि राहुल गांधी ने एक बार अपने विश्वासी मित्रों के बीच कहा भी था कि मोदी को हराने के लिए उनकी ईमानदार नेता वाली इमेज को तोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के लिए किसी भी चुनाव में जीत की राह आसान हो सकती है।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि वह बीजेपी और मोदी को अपनी ओर से तैयार की गई सियासी पिच पर बैटिंग करने को मजबूर नहीं कर पा रहे हैं। पिछले दो आम चुनावों में बीजेपी ने अपने मनमाफिक पिच तैयार की। चुनावी जंग को मोदी बनाम अन्य के रूप में बदला और इस युद्ध में विजेता बनकर उभरी। दोनों ही बार मोदी बनाम अन्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का प्रमुख चेहरा राहुल गांधी रहे। 2024 के आम चुनावों में बीजेपी एक बार फिर मोदी बनाम राहुल की पिच पर ही बैटिंग करने की कोशिश में है, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी की इस कोशिश को समझ रहे हैं।

बात राहुल गांधी की कि जाए तो राहुल गांधी के सलाहकार जिस तरह की सलाहें देकर उनसे जैसे बयान उनसे दिलवा रहे हैं, उससे देश में एक संदेश जरूर जा रहा है कि राहुल परिपक्व राजनेता नहीं हैं। भारत में लोकतंत्र को कुचले जाने का बयान वह ब्रिटेन में दे ही चुके हैं। लगे हाथों वह ब्रिटेन और अमेरिका से भारत में लोकतंत्र का गला घोंटे जाने पर ध्यान देने की बात भी कर चुके हैं। इस पर उठे बवंडर के बीच उनके बड़े से बड़े समर्थक के लिए उनका बचाव कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, पार्टी के नेताओं की भी किरकिरी हो रही है।

एक तरफ मोदी और राहुल के बीच जुबानी जंग चल रही है तो दूसरी ओर गैर कांग्रेसी दलों के बीजेपी विरोधी नेता इसे बीजेपी की सियासी साजिश बता रहे हैं। इन नेताओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 2024 के लोकसभा चुनाव को मोदी बनाम राहुल बना करके चुनावी बढ़त बनाने की रणनीति बना रहा है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो यहां तक कहती हैं कि राहुल के जरिए बीजेपी, मोदी की टीआरपी बढ़ा रही है। लोकसभा चुनाव अगर मोदी बनाम राहुल के बीच फंस जाता है तो इसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और उसकी सत्ता में पुन: वापसी हो जाएगी क्योंकि आज की तारीख में मोदी के सामने राहुल गांधी कहीं टिकते नहीं हैं। राहुल का बड़बोलापन बीजेपी के लिए प्लस प्वाइंट साबित हो रहा है। राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना बीजेपी को फायदा होता है।

बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की कोलकता में मुलाकात हुई थी। अखिलेश ने अबकी से कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। जहां वह ममता बनर्जी से भी मिले थे और गैर कांग्रेसी-गैर बीजेपी तीसरा मोर्चा बनाने की ममता से चर्चा की थी। इसी दौरान ममता ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि अगर राहुल विपक्ष का चेहरा हैं तो फिर कोई भी नरेन्द्र मोदी को खराब नहीं कह पाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि राहुल गांधी, मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं। इन दिनों जब भाजपा इस बात पर जोर दे रही है कि राहुल गांधी लंदन वाले अपने बयान के लिए माफी मांगें तब कांग्रेस यह बताने में लगी हुई है कि 'वह सावरकर नहीं हैं।' सावरकर को कोसना राहुल गांधी का प्रिय शगल है, लेकिन इसमें संदेह है कि वह अपने इस शगल से एक परिपक्व नेता के तौर पर अपनी छवि स्थापित करने में समर्थ हो जाएंगे। वास्तव में वह अपनी ऐसी छवि बना ही नहीं पा रहे हैं और इसीलिए वे विपक्ष की ताकत नहीं बन पा रहे हैं। कांग्रेस के लिए यह कहना मजबूरी हो सकती है कि राहुल भविष्य के नेता हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा कुछ कहना जरूरी नहीं समझ रहा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल की भागीदारी को लेकर चाहे जितनी प्रशंसा की जाए, इस यात्रा के समाप्त होने के बाद के घटनाक्रम ने उनकी छवि को वैसा ही बना दिया है, जैसी इस यात्रा के पहले थी। अपनी इस छवि के साथ वह कांग्रेस के सर्वोच्च नेता बने रह सकते हैं, लेकिन विपक्ष के नहीं बन सकते। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि एक-एक करके विपक्षी नेता इसी निष्कर्ष पर पहुंचते जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को आईना दिखाया लेकिन कांग्रेस यह बात समझने की जगह ममता पर हमलावर हो गई है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर पलटवार करते हुए यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके बीच राहुल को बदनाम करने के लिए समझौता हुआ है। उनकी मानें तो ममता बनर्जी स्वयं को ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से बचाना चाहती हैं, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ हो गई हैं। इस आरोप-प्रत्यारोप से यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस करीब नहीं आने वालीं।

लब्बोलुआब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या यूं कहें कि मोदी और राहुल के बीच इस समय सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इस घमासान की नित्य नई स्क्रिप्ट लिखी जाती है। दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है वह वर्षों बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी-राहुल के बीच कटाक्ष और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला 2014 के लोकसभा चुनाव के कुछ समय बाद शुरू हुआ था और दस वर्षों के बाद 2024 के चुनाव करीब आने तक जारी है। अब तो यह लड़ाई संसद तक में पहुंच चुकी है। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए कुछ विवादित बयानों को आधार बनाकर बीजेपी उन पर न केवल हमलावर है, बल्कि राहुल से संसद में माफी की मांग करते हुए सत्ता पक्ष संसद की कार्रवाई भी नहीं चलने दे रहा है, इसके उलट कांग्रेस मोदी-अडाणी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी बनाए जाने को लेकर अड़ी हुई है। यही वजह है कि 13 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र कामकाज बिलकुल ठप्प पड़ा है। इस सत्र में आम बजट पर चर्चा और उसे पारित करवाने समेत कुछ अहम सरकारी काम निपटाने होते हैं। संसदीय इतिहास में संभवत: कम ही ऐसे मौके आये होंगे जब विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी सदन नहीं चलने दे रहा है, वह भी एक सांसद से माफी की मांग को लेकर। क्योंकि इस समय कांग्रेस में राहुल गांधी की हैसियत एक सांसद से अधिक कुछ नहीं है। बीजेपी की इस चुनावी रणनीति में राहुल को सूरत कोर्ट से मिली दो साल की सजा का भी तड़का लगना तय है। बीजेपी इसके सहारे राहुल गांधी के खिलाफ लगातार हमलावर रहेगी।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

याज्ञवल्क्यापनिषद् (भाग-03)

गतांक से आगे...

संन्यासी को चाहिए कि वह दूसरों की स्त्रियों को न देखता हुआ तथा नगर में न रहता हुआ, त्रिदण्ड, कमण्डलु, भुक्तपात्र (भोजन पात्र), जल पवित्र, शिखा, यज्ञोपवीत आदि सभी बाह्य एवं आन्तरिक प्रतीक चिह्नों को भू: स्वाहा कहकर जल में विसर्जित करता हुआ निरन्तर आत्मा का अनुसंधान करता रहे।

दिगम्बर, (शीत-उष्ण, सुख-दु:खादि) द्वन्द्वों से रहित, परिग्रहरहित, ब्रह्मरूप तत्त्व की प्राप्ति के मार्ग में सम्यक् रूप से लगे हुए शुद्ध हृदय वाले, केवल प्राण तत्त्व को धारण करने के लिए यथा समय स्वच्छन्दतापूर्वक भिक्षा द्वारा उदर-पूर्ति करने वाले, लाभ-हानि की चिन्ता न करते हुए, हाथ के पात्र अथवा खप्पर में माँगकर भोजन ग्रहण करते हुए तथा कमण्डलु का जल पीकर आनन्दपूर्वक विचरण करे। भोजन मात्र इतना ही माँगे, जिससे कि उदर पूर्ति हो जाये, संग्रह करके रखने की आवश्यकता न हो। अपने निवास के लिए बाधारहित कोई एकान्त गुप्त स्थल का चुनाव करे। खाली खण्डहर, देवमन्दिर, तृण आदि की झोपड़ी, वल्मीक, वृक्ष की जड़ के समीप, कुम्हारों की झोपड़ी, यज्ञशाला, नदी का तट, गुफा (खोह) अथवा झरनों के बड़े-बड़े पत्थरों पर हमेशा के लिए घर न बनाते हुए भी निवास करता हुआ, अपने शुभाशुभ समस्त कर्मों को निर्मूल करता हुआ जो संन्यास धर्म से शरीर को त्याग देता है, वह परमहंस के रूप में जाना जाता है। वस्त्रादि से रहित, सभी में एक मात्र ब्रह्म को देखता हुआ किसी भी व्यक्ति को नमन के योग्य न समझते हुए, स्त्री-पुत्रादिकों के प्रति आसक्ति से हीन, लक्ष्य (लक्षणादि से ज्ञात) तथा अलक्ष्य (समाहित व असमाहित अवस्थाओं द्वारा) दोनों का निर्वर्तक (सब कुछ त्याग देने वाला) संन्यासी ही परमेश्वर होता है। इस सम्बन्ध में ये लोक कहे गये हैं। ने अपने से पूर्व ही संन्यास ग्रहण कर लिया हो अथवा जो धर्म तुल् आचार-विचार एवं सम्प्रदाय से जो श्रेष्ठ हो, उसे ही प्रणाम करना चाहिए, किसी अन्य को नहीं। जिस मनुष्य प्रमादी, बहिर्मुखी, विषयों में आसक्त रहने वाले, नीच, कलह प्रिय एवं वेद के आशय (विचार) को दोषपूर्ण प्रतिपादित करने वाले संन्यासी भी देखने में आते हैं। नाम, धाम, काम एवं अवस्था आदि से परे, ऊँचे श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित, अद्वय रूप स्वारान्य में (जिसमें अपने से भिन्न कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता) स्थित, स्थिर मति, आत्म तत्त्व में निष्णात संन्यासी भला कैसे किसी को प्रणाम करे; क्योंकि वह तो सभी में अपना ही रूप देखता है। उसके लिए तो कोई भी कार्य संसार में शेष नहीं रहता। **क्रमश:**

हिंदी पत्रकारिता के प्रति गणेश शंकर विद्यार्थी का समर्पण

श्याम सुंदर भाटिया

गणेश युगीन पत्रकारिता हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णिम काल माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता के पितामह गणेश शंकर विद्यार्थी के बताए या दिखाए रास्ते पर चलकर ही पत्रकारों ने देश और समाज की सेवा की अलख जगाई है। प्रताप के पहले ही अंक में उन्होंने 'प्रताप की नीति' नामक लेख में राष्ट्रीय पत्रकारिता की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे आज भी आदर्श पत्रकारिता के घोषणा पत्र के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने लिखा- समस्त मानव जाति का कल्याण हमारा परमोद्देश्य है। हम अपने देश और समाज की सेवा के पवित्र काम का भार अपने ऊपर लेते हैं। हम अपने भाइयों और बहनों को उनके कर्तव्य और अधिकार समझाने का यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। राजा और प्रजा में, एक जाति और दूसरी जाति में, एक संस्था और दूसरी संस्था में बैर और विरोध, अशांति और असंतोष न होने देना हम अपना परम कर्तव्य समझेंगे।

हिंदी पत्रकारिता के पितामह गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्रकारिता के सफर का श्रीगणेश इलाहाबाद से हुआ। 'स्वराज' अखबार से उर्दू में लिखना शुरू किया, इसी बीच पंडित सुंदरलाल के सानिध्य में वह हिंदी की ओर आकर्षित हुए। हिंदी पत्रकारिता के प्रति विद्यार्थी जी का संकल्प, सेवा और समर्पण बेमिसाल रहा है। सत्याग्रह, जुलूस और सभाओं से लेकर दलीय चुनावी राजनीति में नेतृत्व संभाला, पर अपनी पत्रकारिता को दलीय राजनीति का मोहरा कभी नहीं बनने दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से डटकर लोहा लिया। विद्यार्थी हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। विद्यार्थी जी अपनी अंतिम जेल यात्रा से 9 मार्च, 1931 को लौटे थे, उस समय देश सांप्रदायिक आग में झुलस रहा था। कानपुर में 'हिंदू-मुस्लिम दंगा' हो गया। ऐसी स्थिति में कानपुर में रहना उचित समझा। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार इस भयावह स्थिति में पूरी तरह मौन है। इसे देखते हुए वह सांप्रदायिकता की आग बुझाने के लिए मैदान में कूद पड़े। इसी बीच 23 मार्च 1931 को लाहौर सेन्ट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। फांसी देने का समाचार सुनकर देश भर में जबर्दस्त आक्रोश फैल गया। हिंदू-मुस्लिम दंगों के दौरान हिंसक भीड़ ने 25 मार्च, 1931 को विद्यार्थी की हत्या कर दी। आज अखबार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, हमें रुलाई अपनी असहायता पर आ रही है कि देश को इस तरह आत्महत्या करते देखकर भी हम उसे रोकने में असमर्थ हैं। हमें रुलाई उन लोगों की बुद्धि पर आती है जो समझते हैं कि ऐसे रक्तपात के बिना हम अपनी रक्षा न कर सकेंगे। हमें रुलाई आती है भारत माता का खिन्न मुखमंडल देखकर। 'गांधीजी ने 'प्रताप' के संयुक्त संपादक को तार भेजा था, जिसमें बापू ने लिखा, 'कलेजा फट रहा है तो भी गणेश शंकर की इतनी शानदार मृत्यु के लिए शोक संदेश नहीं दूंगा। उनका परिवार शोक संदेश का नहीं, बधाई का पात्र है। इसकी मिसाल अनुकरणीय सिद्ध हो।' ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी एवम् हम सभी के प्रेरणापुंज गणेश शंकर विद्यार्थी जी को हमारा शत-शत नमन।

लंबे समय बाद बिकने को तैयार है शत्रु संपत्तियां

संदीप अग्रवाल

जब दो देशों में युद्ध होता है या जब किसी देश का विभाजन होता है तो दोनों पक्षों के लोगों पर इसका असर पड़ता है। सुरक्षा, भावनात्मक या अन्य कारणों से वे एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। जितना साजोसामान वे अपने साथ ले जा सकें, ले जाते हैं। फिर भी उनकी बहुत सारी संपत्तियां वहीं रह जाती हैं। जैसे कि इमारतें और जमीनें। इन्हें तो कोई चाहकर भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। ऐसी संपत्तियों की संख्या काफी बड़ी होती है। पहचान के लिए इन्हें शत्रु संपत्तियां कहा जाता है। जब दो देशों में लड़ाई छिड़ती है तो सरकार शत्रु देश के नागरिकों की संपत्ति पर अधिकार कर लेती है, ताकि शत्रु पक्ष युद्ध के दौरान उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए न कर सके।

भारत में भी ऐसी ज्ञात संपत्तियां हजारों की तादाद में हैं। बहुत सी अज्ञात भी होंगी। पारिभाषिक दृष्टि से भारत के संदर्भ में शत्रु संपत्ति का अर्थ है ऐसी संपत्ति, जो देश के विभाजन या फिर भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन के बीच युद्ध के दौरान भारतीय भू-क्षेत्र में रहने वाले लोग भारत में छोड़कर चीन या पाकिस्तान या किसी और देश में चले गए थे और स्थायी तौर पर वहीं बस गए। ऐसा कई बार हो चुका है। 1947 में देश के विभाजन के समय। 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान के युद्ध के समय। इस दौरान भारत में रहने वाले बहुत से लोग चीन और पाकिस्तान चले गए। भारत सरकार ने ऐसे नागरिकों को शत्रु माना

और यहां छोड़ी इनकी चल-अचल संपत्तियों को शत्रु संपत्ति।

वैसे तो कानूनन इन संपत्तियों पर भारत सरकार का ही अधिकार है। लेकिन, कई जगह भारत छोड़कर शत्रु देशों में चले जाने वाले नागरिक, जाने से पहले इन्हें किसी को बेच गए या किसी को इनका संरक्षक नियुक्त कर गए। इस वजह से बहुत सारी संपत्तियों पर अधिकार को लेकर आजादी के बाद से ही काफी विवाद रहा है। हालांकि समाधान के लिए देश में शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 मौजूद है।

1962 के भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी सरकार को ऐसी समस्त शत्रु संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार है। जब्त करने के अलावा सरकार इनके लिए संरक्षक (कस्टोडियन) नियुक्त कर सकती है। लेकिन 1968 से पहले इसमें शत्रु शब्द शामिल नहीं था। इसके बाद भी कई बार शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन कर इसे और अधिक प्रभावी व स्पष्ट बनाने का प्रयास किया जा चुका है। पिछली बार 17 मार्च 2017 को इस कानून में संशोधन किया था। यह एक बहुत महत?वपूर्ण कदम था, जो शत्रु संपत्ति पर मालिकाना हक को नए सिरे से परिभाषित करता था।

इस हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ऐसी तमाम शत्रु संपत्तियों को खाली कराने और इनकी बिक्री की प्रक्रिया शुरू हो जाने की खबरें संकेत दे रही हैं कि इस बार सरकार इस विषय पर दशकों से चल रही उहापोह को खत्म कर इसे एक निर्णायक अंजाम देने के मूड है।

हालांकि सरकार पहले भी ऐसी संपत्तियों की बिक्री करती रही है। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया था कि शेयर व सोना, चांदी जैसी चल शत्रु संपत्ति के निपटान के जरिए सरकार को इस अवधि में 3,400 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई थी। 2018 में भी केंद्र सरकार ने ऐसी संपत्तियों को बेचकर करीब तीन हजार करोड़ रुपये कमाई की थी। लेकिन, अभी तक किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री नहीं हुई है। यह पहली बार होगा, जब अचल शत्रु संपत्तियों की नीलामी भी की जाएगी। सीईपीआई के अंतर्गत आने वाले इन 12,611 प्रतिष्ठानों में से 12,485 पाकिस्तानी नागरिकों से संबंधित हैं और 126 चीनी नागरिकों से।

ऐसी संपत्तियों में करीब आधी (6,255) तो अकेले उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल जहां 4,088 संपत्तियां हैं। बाकी की करीब दो हजार संपत्तियां दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, त्रिपुरा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, मेघालय, असम, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, दमन और दीव, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं।

वर्ष 2020 में गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्तियों के मुद्रीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशों के आधार पर शत्रु संपत्तियों के निपटान से संबंधित दिशा-निर्देशों में बदलाव किया गया है।

नए बदलावों के तहत अब संपत्तियों की बिक्री से पहले संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त की मदद से शत्रु संपत्तियों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि शत्रु संपत्ति की कीमत एक करोड़ रुपये से कम है तो संरक्षक पहले कब्जेदार को संपत्ति खरीदने की पेशकश करेगा और यदि वे इसे अस्वीकार कर देते हैं, तो शत्रु संपत्ति का निपटान दिशानिर्देशों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। हालांकि यह काम आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अधिकांश शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। बहुत सारी जगहों पर भूमाफिया द्वारा शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर पक्की इमारतों या घरों का निर्माण कर दिया गया है। जहाँ पर अनेक परिवार रह रहे हैं। ऐसे में इन्हें खाली कराना चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अलावा, यह शत्रु संपत्तियों की वर्तमान सूची भी कोई अंतिम सूची नहीं है, सीईपीआई इसे अपडेट करती रहती है तो हो सकता है कि जैसे-जैसे ऐसी और संपत्तियों का पता लगता जाए, यह सूची भी लंबी होती जाए। लेकिन, केंद्र सरकार का ताजा फैसला, एक अच्छी शुरुआत तो है ही। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसे राजनीतिक और साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं की जाएगी।

गांधी आज

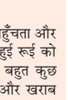

खादी उत्पादन की क्रियाएं (भाग-2)

गतांक से आगे...

हाथ-ओटनी में कपास के बीज को नुकसान नहीं पहुँचता और रूई के रेशों की मजबूती कम नहीं होती। ताजी ओटी हुई रूई को धुनना आसान होता है। अच्छी कताई अच्छी पूनी पर बहुत कुछ अवलंबित होती है। जो कातना जानता है वह अच्छी और खराब पूनी का भेद समझता है और जो चुनना जानता है वह उसकी क्रियाओं की बारीकी समझता है अत: धुनना जाननेवाला दूसरे की पूनी का इस्तेमाल लाचारी दर्जे ही करता है।

खराब पूनी सूत के नंबर घटाती और टूटे तारों का बिगाड़ बढ़ाती है; इस कारण आर्थिक दृष्टि से वह बहुत हानिकर है। रूई की किस्म जितना बर्दाश्त कर सके उससे मोटा कातना या अधिक महीन कातना दोनों हानिकर क्रियाएं हैं। पर सामान्यत: कतैयों का रुख मोटा कातने की ओर होता है। इसे रोकने की ज़रूरत है। खादी उत्पादकों को इसका खयाल रखना चाहिए कि रूई की किस्म जितना सह सके उतना ही महीन सूत कताया जाय। 10. सूत पूरे कस का और समान निकले, इसपर भी उत्पादकों को नज़र रखनी चाहिए। महीन सूत के मानी हैं थोड़ी रूई में ज्यादा कपड़ा, कसदार सूत के मानी हैं टिकाऊ कपड़ा और समान सूत का अर्थ है एक-सा और सुंदर कपड़ा। फिर, सूत कसदार और एक-सा हो तो बुनकर कम मज़दूरी पर उसे बुनने को तैयार रहता है। इस कारण खादी सस्ती करने के ये महत्त्वपूर्ण अंग है। खादी सेवक को उत्पत्ति संबंधी सब क्रियाओं का अनुभवयुक्त ज्ञान होना चाहिए। इसके सिवा खादी उत्पत्ति संबंधी सभी यंत्र के गुण-दोष का ज्ञान और उनकी मरम्मत करना भी उसे आना चाहिए। उसे खुद इतना कारीगर होना चाहिए कि गाँव के किसानों को ही नहीं, बढ़ई, लुहार इत्यादि कारीगरों को भी सिखा और राह बता सके। इसके सिवा उसे खादी के आर्थिक अंग का भी ज्ञान होना चाहिए।

राज्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं हमारे किसान-भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री की घोषणा से किसानों में खुशी की लहर, कर रहे धन्यवाद, कहा अब मिलेगा ज्यादा फायदा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा की है । घोषणा के बाद से किसानों में खुशी की लहर है। इस फैसले का स्वागत करते हुए किसानों का कहना है कि अब वे अधिक धान बेच सकेंगे जिससे लाभ भी अधिक होगा। कोरिया जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के जामपारा के किसान कृष्ण रजवाड़े ने घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्होंने पिछले सीजन में 28 क्विंटल धान की बिक्री की है और अभी अपने खेत में टमाटर, गोभी भी उगा रहे हैं। उन्हें पहले ही धान बेचकर काफी फायदा हुआ है, अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदी से ज्यादा धान बेच सकेंगे। पोत्रीडांड के किसान कोलेश्वर सिंह बताते हैं कि उन्होंने इस वर्ष 42 क्विंटल धान बेचा है। मुख्यमंत्री द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढाकर 20 क्विंटल किए जाने से अब उन्हें अतिरिक्त धान को बेचने की चिंता नहीं रहेगी। ग्राम ओड़गी के किसान तेजप्रकाश राजवाड़े बताते हैं कि वे 2.5 एकड़ में धान बोते हैं, पिछली बिक्री 15 क्विंटल की हुई थी। उन्हें और उनके परिवार को जैसे ही इस घोषणा के बारे में पता चला सभी बहुत खुश हुए, क्योंकि इससे हमारे जैसे किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा। इस घोषणा के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि विधानसभा में चर्चा के बाद विनियोग विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान हैं। सम्पूर्ण विश्व आज खाद्य संकट की अग्रसर हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कृषि का अलाभप्रद होना। छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सशक्त बना रही है।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तेजी से हो रहा अमल

बिलासपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में बेरोजगारी भत्ता एवं सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में की गई घोषणाओं पर जिला प्रशासन ने तेजी से अमल शुरू कर दी है। कलेक्टर

श्री सौरभ कुमार ने आज मंथन सभाकक्ष में जनपद पंचायत के सीईओ और रोजगार अधिकारियों की बैठक लेकर शासन के दिशा-निर्देशों से अवगत कराकर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। पात्र बेरोजगारों को 1 अप्रैल से प्रति माह ढाई हजार रूपए भत्ता दिया जाएगा। वहीं सर्वे के उपरांत लोगों को आवास सहित शासन की अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। कलेक्टर ने सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में इन कार्यों को पूर्ण करने कहा है। कलेक्टर ने कहा कि 01 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ हो रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, 01 अप्रैल को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष, 01 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन हो एवं वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से अधिक नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। बेरोजगारी भत्ते स्वीकृत होने या अस्वीकृत होने का आदेश भी ऑनलाईन जारी होगा। उक्त सभी प्रक्रियाओं समुचित क्रियान्वयन के लिए आप सभी अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक तैयारी पूर्ण करें। ऐसे जगहों पर केन्द्र बनाएं जहां पर्याप्त कम्प्यूटर और इंटरनेट की सुविधा हो। साथ ही वहां आने वाले युवाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने 01 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की तैयारी के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जनसामान्य के जीवन स्तर पर प्रभाव का आंकलन कर प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा नई योजनाओं के निर्माण में उपयोग किया जाना है।

प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा से किसान गदगद

■ फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि किसनिहा मुख्यमंत्री ने किसानों के दर्द को समझा

बिलासपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए किसानों से समर्थन मूल्य पर अब प्रति एकड़ 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की गयी है। धान खरीदी की मात्रा 15 से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ किए जाने के फैसले जिले के किसान गदगद हैं। उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब अतिरिक्त धान को औने-पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। किसानों ने कहा कि आखिर किसान के दर्द को एक किसनिहा मुख्यमंत्री ने समझा। सभी ने एक स्वर में मुख्यमंत्री को बारंबार धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया। सकरी तहसील के बहतराई में रहने वाले किसान श्री संतोष कुमार कौशिक ने इस घोषणा को किसानों के हित में लिया गया बड़ा निर्णय बताया। उन्होंने बताया कि वे दो एकड़ में खेती करते हैं और लगभग 40 क्विंटल धान की पैदावार होती है। 15 क्विंटल के बाद बाकी का धान औने-पौने दाम पर बाजार में 1200 क्विंटल में बेचते थे। इस फैसले से प्रति क्विंटल हमें 20 से 25 हजार रूपए की बचत होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जहां किसानों के हित में ऐसा निर्णय लिया गया है। अमेरी गांव के श्री मनहरण लाल निर्मलकर ने बताया कि उनके पास पांच एकड़ खेत है। उन्होंने इस फैसले को किसानों के लिए फायदेमंद बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। निरतू गांव की श्रीमती कला बाई ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू से किसानों के बेहतरी के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इस घोषणा से अब हमें औने-पौने दाम पर अपने धान को बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। बहतराई के श्री लक्ष्मी प्रसाद कौशिक ने बताया कि वे पौने दो एकड़ भूमि में खेती किसानी करते है।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त धान को औने पौने दाम में बेचना पड़ता था, जिससे हमें नुकसान होता था। सरकार द्वारा दी जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त से हम बच्चों की परवरिश और अपने सारे त्यौहार अच्छे से मना पा रहे है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। तखतपुर ब्लॉक के चिचिरदा निवासी श्री बद्रीप्रसाद ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए इसे किसानों के हित में लिया गया बड़ा निर्णय बताया है।

संक्षिप्त समाचार

जल संरक्षण करने ग्रामीणों को किया गया प्रेरित

बिलासपुर। जल जीवन मिशन अंतर्गत विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम बन्नाकडीह में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान सोसायटी के सदस्यों द्वारा ग्रामीणों को जल के रख-रखाव, संरक्षण एवं संवर्धन के विषय में जानकारी देते हुए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को जल के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में ग्रामीणों की सामुदायिक सहभागिता एवं जलकर वसूली के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। वर्षा जल के संचय, रूफरेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं सोख्ता गड्ढा बनाने हेतु ग्रामवासियों को प्रेरित भी किया गया। कार्यक्रम में अभियान सोसायटी के टीम लीडर श्री विनोद सिंह, नोडल अधिकारी श्री पी.के.महतो, क्राडिनेटर सुश्री हिमांगी बघेल, डब्ल्यूक्यूएमएस के क्राडिनेटर सुश्री सध्या बंदे सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने महिला पर्वतारोही को दी 5 लाख की आर्थिक सहायता

बिलासपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ग्राम भरनी निवासी महिला पर्वतारोही कुमारी निशु सिंह को स्वेच्छानुदान मद से 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। तहसील कार्यालय सकरी में आज जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार ने उक्त राशि के चेक निशु सिंह को सौंपे। बिलासपुर की निशु सिंह छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध माउंटेनियर है। उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों में से एक किलिमंजारो सहित हिमालय के कई चोटियों पर विजय हासिल की हैं। उनकी इच्छा निकट भविष्य में माउण्ट एवरेस्ट चढ़ाई करने की है। इसकी तैयारी एवं संसाधन एकत्र करने में वे जुटी हुई हैं। उन्होंने एवरेस्ट अभियान में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति आभार प्रकट किया है।

विश्व क्षय रोग दिवस पर विशेष शिविर आयोजित

बिलासपुर। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर कोटा के कोटसागर पारा मेडिकल मोबाइल यूनिट द्वारा विशेष शिविर लगाया गया। शिविर में डॉक्टर आकांक्षा पमनानी के द्वारा लोगों को क्षय रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही क्षय रोग के रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया गया इस अवसर पर एरिया प्रोजेक्ट मैनेजर श्री बालकृष्ण तिवारी, जिला समन्वयक श्री तुषार वैद्य, फार्मासिस्ट श्री प्रवीण साहू, नर्स सुश्री रिहाना बेगम, लैब टेक्नीशियन सुश्री आरती एवं वाहन चालक श्री अशोक वैष्णव उपस्थित थे।

कर्मा महोत्सव का आयोजन संपन्न

पाटन। पाटन विधानसभा क्षेत्र के प्रथम ग्राम रीवागहन (ब)में स्थानीय साहू समाज के तत्वाधान में भक्त माता कर्मा जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन कलश यात्रा पश्चात पूजा अर्चना कर खिचड़ी का भोग चढ़ाया गया।सामाजिक बंधुओं के द्वारा खेलकुद एवम् प्रतिभा सम्मान किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि अशोक साहू उपाध्यक्ष ज़िप दुर्ग थे। अध्यक्षता छगन साहू सचिव परिक्षेत्र बेल्हारी ने की।विशेष अतिथि कपूर साहू सेक्टर प्रभारी,देवकी साहू सरपंच,जगदीश साहू,रूखमणी साहू, पुरानिक साहू,देवेंद्र साहू, मया राम साहू,संजय साहू पूर्व सैनिक,भूपत साहू रहे।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तेजी से हो रहा अमल

बिलासपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में बेरोजगारी भत्ता एवं सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में की गई घोषणाओं पर जिला प्रशासन ने तेजी से अमल शुरू कर दी है। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने आज मंथन सभाकक्ष में जनपद पंचायत

के सीईओ और रोजगार अधिकारियों की बैठक लेकर शासन के दिशा-निर्देशों से अवगत कराकर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। पात्र बेरोजगारों को 1 अप्रैल से प्रति माह ढाई हजार रूपए भत्ता दिया जाएगा। वहीं सर्वे के उपरांत लोगों को आवास सहित शासन की अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। कलेक्टर ने सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में इन कार्यों को पूर्ण करने कहा है। कलेक्टर ने कहा कि 01 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ हो रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, 01 अप्रैल को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष, 01 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन हो एवं वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से अधिक नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। बेरोजगारी भत्ते स्वीकृत होने या अस्वीकृत होने का आदेश भी ऑनलाईन जारी होगा।

बस्तर में राजनेताओं पर लाल आतंक का खतरा नक्सलियों ने कांग्रेसी नेताओं को दी चेतावनी

नारायणपुर। खोड़गांव मुख्य मार्ग पर नक्सलियों ने शुक्रवार को बैनर लगाकर जनप्रतिनिधियों को चेतावनी दी है. नक्सलियों ने पांच लोगों के नाम लिखकर उन्हें कॉरपोरेट घराने का दलाल बताया है. इस बैनर में बिसेल नाग, लहर सिंह, कोड़ेनार सरपंच पटेल, कांग्रेस के नेता अध्यक्ष अमित भद्र और अन्य दलालों को जनता दरबार में माफी मांगने को कहा गया है. ऐसा नहीं करने पर सागर साहू जैसा अंजाम भुगतने की बात कही गई है. इस घटना की पुष्टि एसपी ने की है.कांग्रेसी नेताओं को नक्सलियों की चेतावनी = नक्सलियों के बैनर में कांग्रेसी

नेताओं के नाम लिखे गए हैं. जिसमें खोड़गांव सरपंच बिसेल नाग, छोटेडोंगर परगना अध्यक्ष लहर सिंह,युवा नेता अमित भद्र का नाम लिखा गया है. इस बैनर के माध्यम से पहले जारी किए गए बैनर की भी बात लिखी गई है. आपको बता दें कि छोटेडोंगर में बीते माह भाजपा नेता सागर साहू की हत्या नक्सलियों ने की थी.जिसके बाद बस्तर में माहौल काफी गर्म हो गया था.लगातार हो रही नक्सली वरदात = बैनर मिलने के दो दिन पहले खोड़गांव के आश्रित गांव अंजरेल में भी नक्सली हिंसा हुई थी. जहां वर्दीधारी नक्सली माइंस एरिया अंजरेल में पहुंचे और सड़क निर्माण कार्य को बंद कराया था. इस दौरान, वहां काम कर रहे श्रमिक और मुंशी को काम दोबारा शुरु नहीं करने की चेतावनी देकर नक्सलियों ने उन्हें छोड़ा था. जाते जाते नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहन, पानी टैंकर, पिकअप वाहन और मिक्सर मशीन में आगजनी की थी. एक बार फिर नक्सलियों ने राजनेताओं को धमकी दी है. जिससे इलाके में डर का माहौल है।

राज्यपाल वन वर्ल्ड टी. बी. सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल हुए

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 'वन वर्ल्ड टी. बी. सम्मेलन' में मुख्य

अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर टी. बी. मुक्त भारत अभियान के तहत नई पहल कार्यक्रम की शुरूआत की गई और राज्यों और जिला स्तर के अधिकारियों को टी. बी. मुक्त भारत अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन सहित सभी राज्यों के राज्यपाल एवं स्वास्थ्य मंत्री भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को भारत फलीभूत कर रहा है। भारत ने 2025 तक टी. बी. मुक्ति करने का संकल्प लिया है जो जनभागीदारी से ही सम्भव होगा। पूरे विश्व में 2030 तक टी. बी. से मुक्ती का लक्ष्य रखा गया है जबकि भारत ने इससे पांच साल पूर्व ही टी. बी. समाप्ति का प्रण लिया है। श्री मोदी जी ने कहा कि टी. बी. हारेगा और देश जीतेगा। यह प्रयास सबके समन्वय से पूर्ण होगा।

राहुल गाँधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है - चौधरी

रायपुर। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा रायपुर जिला अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा है कि अदालत का फैसला यह दर्शाता है कि देश का क़ानून और देश का संविधान सबसे ऊपर है और उसकी नजर में देश के सभी नागरिक समान हैं। अदालत का निर्णय यह भी सिद्ध करता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि उसने अपराध किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी।

राहुल गाँधी ने देश के ओबीसी समाज के बारे में जो अनर्गल और आपत्तिजनक बातें 2019 के चुनाव में की थी, उसकी हम सब ने तब भी निंदा की थी, आज भी निंदा कर रहे हैं क्योंकि उनकी बातें काफी अपमानजनक थी। अदालत द्वारा सजा सुनाने के बावजूद जिस तरह से राहुल गाँधी और कांग्रेस पार्टी के नेता उन अपमानजनक बातों को सही ठहरा रहे हैं, वह बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मंशा क्या है और देश के ओबीसी समाज के बारे में उनकी सोच क्या है। राहुल गाँधी अभी भी राजशाही सोच से बाहर नहीं निकले हैं। क्या देश की जनता के खिलाफ देश के एक बड़े नेता का ऐसा निंदनीय बोलना उन्हें शोभा देता है? क्या यह देश के संविधान का अपमान नहीं है? क्या यह आत्मसम्मान के साथ जीने वाले सभी गरीब लोगों का अपमान नहीं है? क्या राहुल गाँधी देश से और देश के संविधान से इतने बड़े हो गए हैं कि हमें गाली देने का उन्हें अधिकार मिल गया है? माफी मांगना तो दूर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित कांग्रेस के तमाम नेता जिस तरह से इसे सही ठहराने में जुटे हुए हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि वे हमारा अपमान ही अपना नैतिक धर्म समझते हैं। राहुल गाँधी ये मानना छोड़ दें कि वह और उनका परिवार देश से ऊपर है। यदि राहुल गाँधी और देश की जनता को लगता है कि वे देश के संविधान और देश के क़ानून से ऊपर हैं तो ये उनकी भूल है। राहुल गाँधी जी और कांग्रेस के नेता यदि मानते हैं कि वे अपने ही देश के नागरिक को अपशब्द कह सकते हैं तो देश की जनता को भी देश के संविधान ने आपके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार दिया है।

चौरसिया महासभा का आयोजन 26 मार्च को

रायपुर। अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत संस्था है जो कि समूचे भारत वर्ष में फैले हुए चौरसिया बंधुओं को एक छत को नीचे लाने हेतु पिछले लगभग 40 वर्षो से प्रयासरत हैं। आमतौर पर पान की खेती और पान का व्यवसाय करने वाले ही इस समाज के लोग हैं। संस्था के संविधान के अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष में नया चुनाव होता है। अभी तक संविधान के अनुसार मात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही चुनाव होता है। और उन्हें अधिकृत किया जाता है। कि वे अपनी टीम का चयन या मनोनयन स्वयं करें। प्रत्येक तीन वर्ष में देश के अलग-अलग प्रदेशों में राष्ट्रीय महासभा होता है। हर्ष का विषय है कि इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को इस महासभा के आयोजन का सुअवसर दिया गया है , 25 और 26 मार्च निरंजन धर्मशाला व्ही. आई.पी. रोड़ में इसका आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय चुनाव हेतु आम सभा का आयोजन तो 26 मार्च को सुबह 9.00 बजे से है। मगर देश भर से लोग 25 तारीख से ही आ जाएँगे। 25 तारीख को संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। 26 मार्च को चुनाव के बाद पुलिस बैंड का आनंद भी लोग ले सकेंगे। चौरसिया वेलफेयर सोसाइटी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा पत्रकार वार्ता में उक्त जानकारी दी गई।

छत्तीसगढ़ मना रहा मिलेट्स त्यौहार

पोषण के पावर हाउस मिलेट्स के फायदों के बारे में लोगों को किया जा रहा जागरूक

रायपुर। बच्चों तथा महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जागरूकता और आदतों में सुधार लाने के लिए प्रदेश में 20 मार्च से पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 03 अप्रैल तक चलेगा। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इंटरनेशनल मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए इस साल पोषण पखवाड़ा को छत्तीसगढ़ में मिलेट्स त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को पोषण के पावर हाउस मतलब मिलेट्स के फायदों के बारे में जानकारी देकर उन्हें इस पारम्परिक पौष्टिक अन्न को दैनिक आहार में शामिल करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए विशेष थीम के अनुसार कई कार्यक्रम

आयोजित किए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि मिलेट्स (मोटे अनाज) जैसे कोदो, कुटकी, रागी एक पौष्टिक खाद्य विकल्प हैं जो दैनिक पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। यह शिशुवती महिलाओं के लिए भी बेहद फायदेमंद होते है। इनमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स जैसे पोषक तत्व प्रचुरता से होते हैं। इसे देखते हुए पोषण कल्याण के लिए श्री अन्न अर्थात् मिलेट्स का प्रचार-प्रसार कर उसकी लोकप्रियता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा के अंतर्गत छह वर्ष तक के बच्चों का वजन, लंबाई एवं ऊंचाई मापन कर बच्चों में पोषण स्थिति की जानकारी भी ली जा रही हैं। सक्षम आंगनबाड़ी के प्रति जनसमुदाय को जागरूक करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। पोषण पखवाड़े के प्रत्येक दिन के लिए कलेण्डर अनुसार गतिविधियां निर्धारित की गई है। इसके अनुसार प्रतिदिन अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर पोषण सम्बन्धित व्यवहार परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। इन समस्त गतिविधियों को पोषण ट्रैकर ऐप में प्रतिदिन इन्द्राज भी किया जा रहा है।

पोषण जागरूकता के लिए प्रदेशभर में जागरूकता रथ, बाइक रैली निकाली जा रही हैं। प्रमुख पंचायतों एवं हाट-बाजारों में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं देखभाल संबंधी उचित आदतों के विकास एवं सुधार के संबन्ध में वीडियो क्लिप का प्रदर्शन करते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, ग्राम पंचायतों में लोगों को सुपोषण के संबंध में जानकारी दी जा रही हैं और मिलेट्स को आहार में शामिल करने के फायदे समझाए जा रहे हैं। मिलेट्स से बने व्यंजनों की प्रतियोगिता, प्रदर्शनी एवं मिलेट्स जागरूकता कैम्प भी आयोजित किए जा रहे हैं। कई स्वसहायता समूह मिलेट्स से बने तिरंगा थाली के प्रदर्शन से मिलेट्स का महत्व बता रहे हैं। पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत समुदाय आधारित गतिविधियों जैसे-सुपोषण चौपाल, महिला समूहों की बैठक, पालको का बैठक करना तथा लिंग संवेदनशील, जल प्रबंधन, एनीमिया की रोकथाम व प्रबंधन के प्रति जागरूकता कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है। इसमें स्वास्थ्य, पंचायत सहित विभिन्न विभागों का समन्वय भी लिया जा रहा है।

तेरे वजूद में गुरुर है तो मेरे वजूद में खुद्दारी है.....

विदेश में राहुल गाँधी ने देश का अपमान किया है उन्हें संसद में माफ़ी मांगना चाहिये इस मांग को लेकर सत्ता पक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है तो कॉंग्रेस सहित विपक्ष संसद में माइक बंद करने का आरोप लगा रहा है। बहरहाल संसद की कार्यवाही में गतिरोध क़ायम है। लोकसभा में शुक्रवार को सांसदों का माइक बंद हो जाना ऐसे ही क्षणों में से एक है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को बोलने देने की मांग जैसे ही शुरू की तो माइक बंद हो गए और अध्यक्ष मुस्कुरा कर इसे देखते रहे। यह संयोग था कि संकेत है? भारत में लोकतंत्र खत्म करने की जो बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत के गांवों से लेकर सुदूर इंग्लैंड तक कर रहे रहे थे, मोदी सरकार ने उस पर अंतिम मुहर लगा दी है..? इस संकेत को अगर देश नहीं समझ पा रहा है तो इसके पीछे सरकार समर्थक मीडिया और सरकार का मजबूत प्रचार-तंत्र है।उनकी भूमिका का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने इसे एक तकनीकी खराबी बता कर झट से ढंक दिया। क्या देश को संचालित करने वाली सर्वोच्च संस्था का एक महत्वपूर्ण क्षण पर मौन हो जाना गुस्सा का सबब नहीं होना चाहिए? यह भी उस समय होता है जब सरकार विपक्ष के एक प्रमुख नेता पर देशद्रोह का आरोप लगा रही है और वह अपना जवाब देना चाहता है।दिलचस्प यह है कि घटना के पीछे तकनीकी खराबी होने की खबर भी सूत्रों के हवाले से आई है। अभी तक कोई अधिकारिक बयान नहीं आया.....? इतनी बड़ी चूक के लिए किसी ने माफी नहीं मांगी.....अगर हम थोड़ी देर को यह मान भी लें कि विदेशी धरती पर राहुल के बयान देश के खिलाफ थे तो क्या उनका पक्ष सुने बगैर उन्हें सजा दे दी जाए.....? लोगों ने सत्ता पक्ष की चालाकी को नहीं देखा कि मोदी सरकार के मंत्रियों ने राहुल के खिलाफ किसी कानूनी लड़ाई के बदले मीडिया और संसद में मोर्चा खोला है।दोनों जगह फैसले उसके हाथ में हैं। मीडिया में मतदान की जरूरत नहीं है और फैसला पहले से उसके पक्ष में है। संसद में फैसला उसके पक्ष में ही होना है क्योंकि बहुमत उसके पास है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संसद की कार्यवाही की समीक्षा अदालत में नहीं हो सकती है और संसद को अपने अपमान के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है।लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में शुरू से यही तरीका अपनाया है कि राहुल गांधी को संसद में उनका पक्ष रखने नहीं दिया जाए। भाजपा के सांसद और मंत्री संसद में हंगामा करते हैं और विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका आने के पहले ही सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। सत्ता पक्ष यह सुनियोजित ढंग से कर रहा है। भाजपा का आचरण प्राकृतिक न्याय के उस बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है जोआरोपी को अपना पक्ष रखने का अधिकार देता है। माइक बंद करने की कार्रवाई क्या आरोप सिद्ध होने के पहले ही दोषी करार देने की कार्रवाई का हिस्सा है? तानाशाही की इस खुली घोषणा के बाद मीडिया में चल रही इस बहस का कोई अर्थ नहीं रह जाता कि राहुल ने लंदन में क्या कहा था.....इस बहस में सिर्फ भाजपा ही नहीं, कुछ मीडिया हॉउस भी झूठ का सहारा ले रहे हैं। राहुल गाँधी ने कही नहीं कहा कि भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए बाहरी लोग हस्तक्षेप करें। उन्होंने यह भी नहीं कहा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है।उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि भारत का लोकतंत्र दबाव में है और इसे मिटाने वाले काम हो रहे हैं। उन्होंने इंग्लैड में अपने श्रोताओं को लोकतंत्र पर विश्व भर में हो रहे हमलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सोचना चाहिए कि वे अपने मुल्क में इसके लिए क्या करना चाहिए। साथ ही, उन्होंने अपने श्रोताओं को भारत में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी रखने के लिए कहा। राहुल की राय में यह इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र के साये में रहने वाली कुल आबादी का आधा हिस्सा भारत में निवास करता है। सच तो यह है कि राहुल ने लंदन में साफ-साफ कहा कि भारत में जो समस्याएं हैं वे आंतरिक हैं और इसका हल भी देश के भीतर से ही निकलेगा।इधर संसद में बोलने से रोके जाने के बाद उन्होंने विदेश मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में स्पष्ट किया कि जो प्रचारित किया जा रहा है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा।इधर संसदीय परंपरा में यह पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष संसद की कार्यवाही को ठप कर रहा है। संसद में कार्य रोक कर किसी अन्य विषय पर चर्चा कराने का काम विपक्ष का होता है। संसद में विपक्ष की उपस्थिति को सत्ता पक्ष खारिज कर रहा है। यह एक गंभीर बात है। इसे मोदी सरकार के आम रवैये के साथ जोड़ कर देखना चाहिए। प्रधानमंत्री विपक्ष से कभी बात नहीं करते हैं। संसद के साथ भी उनका रवैया वैसा ही है। उन्होंने नीतिगत संबंधी कोई घोषणा संसद में नहीं की है।नोटबंदी हो या फिर लॉकडाउन, वह सारी घोषणाएं संसद से बाहर करते रहे हैं। ये घोषणाएं वह प्रेस के सामने भी नहीं करते हैं और न ही ऐसी घोषणाओं में कैबिनेट के सदस्यों की कोई हिस्सेदारी होती है?मीडिया ने भले ही क्लीन चिट दे रखी हो उनसे यह सवाल तो होना ही चाहिए कि उन्होंने नौ साल के अपने कार्यकाल में कोई प्रेस कांफ्रेंस क्यों नहीं किया।राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समय भी उन्होंने केवल अडानी को लेकर उठाए गए राहुल के ही सवालों का जवाब नहीं दिया बल्कि प्रस्ताव पर बोलने वाले किसी सांसद की बात का कोई नोटिस नहीं लिया। संसद में विपक्ष के किसी सवाल का उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया है। संसद में एक अकेला सब पर भारी वाला डॉयलाग भी चर्चा में रहा है। लोकतंत्र में कोई भी संसद से भारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस-मुक्त भारत और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा क्षेत्रीय दलों की समाप्ति का नारा दे चुके हैं।किसी भी लोकतंत्र में क्या ऐसी कामना कोई पी?म कर सकता है... लेकिन मोदी ऐसा बार बार कह चुके हैं।

राहुल की लोस सदस्यता समाप्त की गईं....

मानहानि केस में सजा मिलने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। राहुल गांधी को दो साल की सजा मिली थी।केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। अगर इस मसले पर राहुल गांधी को स्टे नहीं मिलता है तो वो छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लोकसभा से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई है इसी के बाद यह चर्चा तेज है कि क्या राहुल की सांसदी भी जाएगी...लोक-प्रतिनिधि

अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के मुताबिक अगर किसी नेता को दो साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसे सजा होने के दिन से उसकी अवधि पूरी होने के बाद आगे छह वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है। अगर कोई विधायक या सांसद है तो सजा होने पर वह अयोग्य ठहरा दिया जाता है। उसे अपनी विधायकी या सांसदी छोड़नी पड़ती है। संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि राहुल गांधी को दो साल की सजा जरूर हुई है, लेकिन सजा अभी निर्लंबित है। ऐसे भी फिलहाल उनकी सांसदी पर कोई खतरा नहीं है। राहुल को अगले तीस दिन के भीतर ऊंची अदालत में फैसले को चुनौती देनी होगी। अगर वहां भी कोर्ट निचली अदालत को बरकार रखती है तो राहुल की संसद सदस्यता जा सकती है....?पर राहुल गांधी की लोस सदस्यता समाप्त कर ही दी गईं।

छग मिडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक और भूपेश का वादा पूरा

छत्तीसगढ़ मिडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक विधानसभा में सर्व सम्मति से पारित हो गया। इस विधेयक में स्वतंत्र पत्रकार,मिडिया संस्थान में कार्यरत मिडिया कर्मियों से लेकर गांव में काम करने वाले पत्रकारों को सुरक्षा देने का प्रावधान है। सीएम भूपेश बघेल ने इस चुनावी वादे को निभाकर देश में पत्रकार हित में एक अनुकरणीय कदम उठाया है, इसके लिये वे साधुवाद के पात्र हैं। वैसे पत्रकार हित में उन्होंने सम्मान निधि बढ़ाया, पत्रकार अधिमान्यता का दायरा भी बढ़ाया है, पत्रकारों के आवास के लिये ऋण अनुदान की उन्होंने पहले ही पहल की है। मिडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक छग में लागू करना देश के अन्य प्रदेशों के लिये नजीर बनेगा, यह तय है .... बधाई भूपेशजी।

सुनील का एनडीटीवी से इस्तीफा....

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव सुनील कुमार ने एनडीटीवी बोर्ड के एडीशनल डाइरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने 9 मार्च को अपना त्यागपत्र टीवी चैनल की संचालक कंपनी अडाणी ग्रुप को भेज दिया था। सुनिल कुमार ने अपने इस्तीफा में हाल के कुछ घटनाक्रमों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि एनडीटीवी के साथ अपने जुड़ाव पर पुनर्विचार करने के लिए मुझे प्रभावित किया है।वैसे भी देश की आईएएस लाबी में अपनी कार्यप्रणाली और ईमानदार छवि के लिये जाने,जानेवाले सुनील कुमार को जब एनडी टीवी में एडीशनल डायरेक्टर बनाया गया था तभी उन लोगों को आश्चर्य हो रहा था,जो सुनील को अच्छे से जानते हैं। इधर पूर्व सी?म रमन सिंह के खास एक और पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह भी अडाणी समूह की ओर से एनडीटीवी बोर्ड में एडीशनल डॉयरेक्टर के पद के लिए मनोनित किए गए थे। वे अभी आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में छग के आर्थिक अपराध विभाग के जाँच के दायरे में हैं।

रिटायर अफसरों की मौज है छग में....

छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे शह और मात का खेल तेज होता जा रहा है। अपने पसंदीदा अफसरों को तो सेट किया ही जा रहा है वहीं रिटायरअफसरों को भी समायोजित करने का सिलसिला जारी है। हाल ही में छग मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिसमुख्यालय में एक ओएसडी का पद स्वीकृत किया गया है, सूत्र कहते हैं कि जल्दी ही रिटायर होने वाले एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर को उपकृत करने की तैयारी है...? नान घोटाले में चर्चित सेवा निवृत आईएएस डॉ आलोक शुक्ला को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गईं है तो आदिवासी समाज के एक रिटायर प्रमोटी आईएएस को भी महत्वपूर्ण पद दिया गया है। हाल ही में सेवानिवृत आईएएस निरंजन दास को उसी पद पर संविदा में नियुक्त किया गया है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका पुनर्वास आदेश भी एक सेवानिवृत संविदा अधिकारी ने जारी किया है। छग के मूल निवासी, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड को भी इस सरकार ने नवाचार आयोग का चेयरमैन बना दिया है। मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के पहले ही डॉ रमन सरकार ने रेरा का चेयरमैन बना दिया था और रेरा से रिटायर होते ही उन्हें नवगठित %नवाचार आयोग% का चेयरमैन बना दिया गया और उनकी ही मर्जी पर जल्दी ही रिटायर होने वाले एक आईएफएस की रेरा में ताजपोशी की तैयारी है।

और बस...

- महादेव एप से सट्टा खिलाने के मामले की ईडी जाँच में कौन से 2 एडीशनल एसपी निशाने पर हैं?
- भाजपा नेता यही नहीं समझ पा रहे हैं कि विस चुनाव में टिकट वितरण में किस स्थानीय नेता की चलेगी...?
- कलेक्टरों के तबादले में क्या राजधानी भी प्रभावित होगी?
- छग में विस चुनाव के चलते अचार संहिता लगने के पहले क्या अक्टूबर तक तबादला होता रहेगा..?

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

कांग्रेस को जनता की नहीं सिर्फ अपनी चिंता- चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने समय पूर्व सत्रावसान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक बार फिर कांग्रेस ने इतिहास का सबसे छोटा बजट सत्र पूरा करने के बजाय पहले ही खत्म कर दिया। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से एक भी विधानसभा सत्र पूरा नहीं हुआ। हर सत्र को छोटा करना और उसमें भी जनता के मुद्दों पर चर्चा में व्यवधान उत्पन्न करना कांग्रेस सरकार के जनविरोधी चरित्र का जीवंत उदाहरण है। कांग्रेस को आम जनता की कोई चिंता नहीं है। यह पार्टी लोकहित और लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटने में भरोसा रखती है। इसे केवल अपने और अपनी पार्टी के स्वार्थों से ही सरोकार है। कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल आचरण नहीं करती। नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह उचित नहीं है। जनता की आवाज जनप्रतिनिधि विधानसभा में ही उठाते हैं और इस प्रकार अगर विधानसभा की अवहेलना होगी तो जनता आखिर कहां जाएगी? कांग्रेस नहीं चाहती कि विधानसभा में जनता के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो और जनता की समस्याओं का समाधान हो। कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, कांग्रेस के विधायक भी अपनी सरकार को आइना दिखा रहे हैं, इसलिए यह सरकार मुद्दों से भाग खड़ी हुई। समय के पहले सत्र समाप्त होने से जनता का नुकसान हुआ और लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है।

राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर बोले अरुण साव- संविधान से बड़ा कोई नही

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने कहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को विधिवत कानूनी कार्यवाही के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत समाप्त किया गया है। श्री साव ने कहा कि एक समाज विशेष, वर्ग विशेष के खिलाफ टिप्पणी कर मानहानि करने के लिए सूरत कोर्ट ने विधिवत सुनवाई करने के बाद दो साल की सजा सुनाई है, और संविधान के प्रावधानों के अनुसार राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर सूरत कोर्ट का फैसला आने के बाद से कांग्रेस के नेता जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे है, न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं वह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है।

श्री साव ने कहा कि कांग्रेस के लोगों की हमेशा से यह प्रवृत्ति रही है कि जब भी कोई फैसला या निर्णय उनके खिलाफ होता है तो वे संवैधानिक संस्थाओं और न्यायालय पर प्रश्नचिन्ह उठाते है। कांग्रेस पार्टी न्यायालय के फैसले और आज लोकसभा सदस्यता खत्म करने के निर्णय के खिलाफ जिस तरह से बातें कह रही है, वही सही मायने में लोकतंत्र का अपमान है। यह प्रजांतत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी माफी मांगने के बजाय जिस प्रकार की बातें कह रही हैं, वह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है।

बुड़ेनी में मंडई मेला संपन्न हुआ शराब बिक्री पर रोक जारी

रायपुर । खरोरा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुड़ेनी में आयोजित त्रिदिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह अवैध शराब बिक्री के खिलाफ जारी अभियान व मंडई मेला के साथ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ । इधर ग्राम बुड़ेनी में जारी शराब विरोधी अभियान की आंच अब अवैध शराब बिक्री की वजह से परेशान नजदीकी ग्राम भड़हा भी पहुंचना शुरू हो गया है और यहां भी इसके खिलाफ शीघ्र ही शंखनाद होने की संभावना बुड़ेनीवासी कर रहे हैं । ज्ञातव्य हो कि ग्राम बुड़ेनी में नवनिर्मित मंदिर में सत्ती माता , भैरव बाबा व हनुमान जी के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का त्रिदिवसीय आयोजन किया गया था । प्रथम दिवस देवी पूजन , दूसरे दिन कलश यात्रा व तीसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा , मंडई मेला व रात्रि में महतारी कार्यक्रम के मंचन के साथ संपन्न हुआ । इधर करीबन बीते 15 दिनों से ग्राम में जारी अवैध शराब बिक्री विरोधी अभियान इस बीच भी जारी रहा जिसके चलते बुड़नी में अवैध शराब बिक्री थमा रहा । आयोजित इस समारोह के दौरान ग्राम के महिलाओं, ग्राम प्रमुखों व पंचायत प्रतिनिधियों ने अवैध शराब बिक्री पर रोक की वजह से ग्राम में व्याप्त शांति के मद्देनजर अब हर कीमत पर ग्राम में अवैध शराब बिक्री न होने देने का संकल्प दुहराया । इधर ग्राम बुड़ेनी में ग्रामीणों द्वारा अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान की आंच अब अवैध शराब बिक्री से त्रस्त नजदीकी ग्राम भड़हा में भी पहुंचने लगा है ।

विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 'कल्चरल कनेक्ट योजना'' से कराया अवगत

रायपुर, 24 मार्च (आरएनएस)। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी पहल करते हुए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार की ''छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट'' योजना से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में ''छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट'' योजना की जानकारी देते हुए लिखा है कि इन केंद्रों की स्थापना से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में छत्तीसगढ़ के लोगों के निवास और भ्रमण की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उक्त केंद्रों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से दो एकड़ शासकीय भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ में संस्कृति केंद्र खोलने के लिए भूमि आबंटन की उन्हें भी सहर्ष स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से ऋषिकेश, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल से गिरनार एवं सोमनाथ, ओड़िसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक से पुरी में, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी से तिरूपति में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से शिरडी में, झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से देवघर में, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज एवं मथुरा में दो एकड़ शासकीय भूमि आबंटित करने का अनुरोध

किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के निर्णय का कांग्रेस ने किया स्वागत

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किसानों से आगामी खरीफ सीजन में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा का कांग्रेस ने स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने आगामी खरीफ सीजन में किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय लिया है, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आयेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश के किसानों को धान की कीमत 2500 रु. प्रति क्विंटल देने का वादा किया था जिसे पूरा किया हैं। इस वर्ष प्रदेश के किसानों की धान 2640 रु. एवं 2660 रु. की दर पर खरीदी गई है। आगामी खरीफ सीजन में किसानों से 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी और लगभग 2800 रु. प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी। छत्तीसगढ़ के किसान देश के सबसे खुशहाल किसान हैं। भूपेश सरकार में 20 लाख किसानो की 11 हजार करोड़ का कृषि ऋण माफ हुआ है, 350 करोड़ का सिंचाई कर माफ हुआ है, 5 लाख से अधिक स्थाई पंप कनेक्शन दिए गए हैं और किसानों के बेहतरी के लिए राज्य की सरकार योजना बनाकर काम कर रही है। बीते 4 वर्ष में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में राज्य सरकार ने डाले है।

भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, आपस में भिड़े कार्यकर्ता

रायपुर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। शुक्रवार को सैकड़ों कार्यकर्ता राजधानी में रजबंधा मैदान स्थित भाजपा दफ्तर एकात्म परिसर पहुंचे, और वहां जमकर हंगामा मचाया। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश भाजपाध्यक्ष अरूण साव की तस्वीर पर कालिख पोत दी। इस बीच भाजपा कार्यालय में बैठे युवा बाहर निकले और युवकों ने वहां लगे झंडे का डंडा निकाल लिए और आपस में भिड़ गए। इस बीच युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी का पूतला फूंक दिया। हालात बिगडने् के बाद एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अतिरिक्त बल की तैनाती की है और माहौल को शांत कराने का प्रयास किया। भाजपा कार्यालय में हुए हंगामे के बाद विवाद बढ़ता देख पुलिस के अतिरिक्त बल की तैनाती कांग्रेस भवन के बाहर भी कर दी गई। कांग्रेसी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में राजीव भवन पहुंचने लगे हैं। भाजपा

कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस भवन जाकर हंगामा करने की धमकी दी है। कार्यालय में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता जबरिया भाजपा कार्यालय में घुसकर हमला करना चाहते थे। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका कानून व्यवस्था का हाल बुरा है।

तानाशाही नहीं चलेगी - भूपेश

रायपुर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त किए जाने और सूरत कोर्ट द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह तानाशाही है और तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाह शासक को उसकी गद्दी जाने का भय रहता है और ऐसे में वह इसी प्रकार का कदम उठता है ताकि लोग उससे डरते रहे। उन्होने अपने ट्वीट में कहा कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद न कर दें. आप उसे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा है डरो मत, इंदिरा जी के साथ भी यही भूल की थी कुछ लोगों ने, बाकि फिर इतिहास है. यहीं मिलेंगे जनता की अदालत में.जनता होगी, जननेता होगा..नहीं होगा तो सिर्फ़ डर और तानाशाह।

कांग्रेसियों ने प्रदेश को अशांत बनाने का षड्यंत्र रचा - अरुण

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में मारपीट की और दीवारों पर व उपस्थित कार्यकर्ताओं पर कालिख फेंकी, वह कांग्रेस का नितांत अलोकतांत्रिक आचरण है। श्री साव ने कहा कि सत्तावादी अहंकार में चूर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश को अशांत बनाने का षड्यंत्र रचा है। श्री साव ने कहा कि भाजपा कार्यालय के सामने मारपीट करते, कालिख फेंकते और प्रधानमंत्री का पुतला दहन करते कांग्रेस के लोगों को पुलिस बल का पूरा संरक्षण प्राप्त था। श्री साव ने कहा कि कांग्रेस के लोग अपने प्रतिकूल किसी भी निर्णय पर जिस तरह की राजनीतिक असहिष्णुता का प्रदर्शन कर अमर्यादित और अलोकतांत्रिक आचरण कर रहे हैं उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री साव ने कहा कि कांग्रेस के लोग प्रदेश की राजनीतिक सद्भावना और शांति व्यवस्था को क्षति पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं यह दुर्भाग्यजनक है।राहुल गांधी की भक्ति में कांग्रेस नेता सारी मर्यादाएं तोड़ रहे है।

राजीव भवन में भाजपाईयों का हमला निंदनीय-कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भाजपाईयो का हमला बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बड़ी संख्या में भाजपाई नुकीले पत्थर और धारदार हथियार, लाठी डंडा लेकर हमला करने आये थे। राजीव भवन पर पथराव किया गया जिससे राजीव भवन की खिड़कियों के कांच टूट गये, गेट पर लगा लेमपोस्ट टूट गया, राजीव भवन में उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मचारियों को चोटे भी आई। यह भाजपा का आतातायी और अतिवादी चरित्र है। प्रजातंत्र में विरोध की अपनी मर्यादा होती है, हिंसक प्रदर्शन सर्वथा अस्वीकार्य है। भाजपाईयों ने सारी मर्यादाओं को तार-तार कर कांग्रेस मुख्यालय पर हमला बोला। कांग्रेस जनों ने भाजपा के इस आतंकी व्यवहार के समय अपना संयम नहीं खोया, इसलिये अप्रिय स्थिति निर्मित होने से बच गयी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा का चरित्र पूरे देश में अलोकतांत्रिक और असहिष्णु हो गया है, अपने खिलाफ उठने वाली आवाज का दमन करने भाजपाई किसी भी स्तर तक गिर सकते है।

नियमितीकरण को लेकर पंचायत सचिवों में नाराजगी

रायपुर। प्रदेश सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र को अमल में नहीं लाए जाने से पंचायत सचिवों में नाराजगी है. जिसको लेकर 16 मार्च से फ़िंसेस्वर ब्लाक मुख्यालय के 72 ग्राम पंचायतों के सचिव अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं। पंचायत सचिवों के अनिश्चित कालीन आंदोलन में होने से मुख्यालय के पंचायतों में ताला लटक गया है. ताला लटकने से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोबर खरीदी ठप होने के साथ ही केंद्र सरकार की रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों का काम भी बंद है. केंद्र व प्रदेश सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ठप होने से ग्रामीणों को रोजी रोटी के लिए काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जानकारी के अनुसार, पंचायत सचिवों के हड़ताल में चले जाने से शासन के महत्वकांक्षी योजना गोबर खरीदी, रीपा कार्य, गौठान के समस्त कार्य, मनरेगा के कार्य, जन्म-मृत्यु पंजीयन, राशनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तरर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, श्रद्धांजलि योजना, पेयजल व्यस्था, शौचालय निर्माण, वन अधिकार पट्टा वितरण, स्वामित्व योजना सर्वेक्षण, ग्राम सभा, बजट निर्माण, समस्त निर्माण कार्य एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह होने से लेखा जोखा के कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.